लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

शुक्रवार, 28 अगस्त , 2026

वर्ष : 12 । अंक: 4

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे समय में अभिमान न करें और कठिन समय में चिंता न करें।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

संक्षेप

बुखार-खांसी में भूलकर भी न खाएं एंटीबायोटिक, स्वाइन फ्लू पर डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू (।।1ह1) का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। मौसम में बदलाव के साथ ही अस्पतालों की ओपीडी में बुखार, खांसी-जुकाम, सिरदर्द और बदन दर्द के मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में कई लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय सीधे मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक खरीदकर खुद ही अपना इलाज कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो तुरंत सावधान हो जाइए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि बिना टेस्ट कराए खुद से एंटीबायोटिक लेना आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. कुलदीप कुमार का कहना है कि खांसी, जुकाम और बुखार के साथ ओपीडी में आ रहे मरीजों में कई लोग स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि स्वाइन फ्लू इन्फ्लूएंजा 'ए वायरस से होने वाला संक्रमण है, यह कोई बैक्टीरियल बीमारी नहीं है। एंटीबायोटिक दवाएं केवल बैक्टीरिया को मारती हैं, वायरस पर इनका कोई असर नहीं होता। बुखार में बिना जरूरत एंटीबायोटिक खाने से शरीर में 'एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस' पैदा हो जाता है, जिससे भविष्य में किसी गंभीर बीमारी के दौरान असली संक्रमण पर भी ये दवाएं काम करना बंद कर देती हैं। स्वाइन फ्लू की चपेट में आने पर मरीज को 100 से 104 डिग्री तक तेज बुखार, सूखी खांसी, गले में दर्द, बंद नाक, सिरदर्द, शरीर में टूटन और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में सांस लेने में भारी तकलीफ भी देखी जाती है।

गंगा बैराज के पास ट्रेनी विमान क्रैश,ट्रेनर और ट्रेनी पायलट की मौत

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक विमान हादसा हो गया। गंगा बैराज के पास नत्था पुरवा गांव में एक ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार ट्रेनर और ट्रेनी पायलट की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार विमान ट्विन इंजन वाला था। बताया जा रहा है कि विमान उड़ान पर था, इसी दौरान अचानक उसमें तेज धमाका हुआ। धमाके के बाद विमान अपना संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते जमीन पर जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार दोनों लोग बाहर नहीं निकल सके। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान गुजरात निवासी सचिन भाटिया और कर्नाटक निवासी अभिषेक पुजारी के तौर पर हुई है। सचिन भाटिया ट्रेनर के रूप में विमान में मौजूद थे, जबकि अभिषेक पुजारी ट्रेनिंग ले रहे थे। विमान दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। हादसे के बाद आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। राहत और बचाव से जुड़ी कार्रवाई के साथ घटनास्थल की जांच भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उड़ान के दौरान विमान में धमाका किस वजह से हुआ और इसके बाद वह दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ। पुलिस और संबंधित अधिकारी हादसे के कारणों की जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।

पीएम मोदी ने 'खेलो इंडिया डायलॉग' में एथलीटों से किया संवाद, कहा-

'मुझे देश के युवाओं की शक्ति पर भरोसा'

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'खेलो इंडिया डायलॉग - खेल की बात, प्रधानमंत्री मोदी के साथ' के तहत गुरुवार को युवा एथलीटों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि जो खेलेगा वो खिलेगा। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि खिलाड़ियों के नाम से ही उनके राज्य और शहर की पहचान होती है। पीएम ने साथ ही सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई भी दी।

यह इवेंट राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के मौके पर 1,500 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों में वर्चुअली आयोजित किया गया। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, जाने-माने मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले संस्थान हैं। यह पहल चार बड़े क्षेत्रों पर फोकस कर रही है, जमीनी स्तर पर खेल संरचना को मजबूत करना, कोचिंग और प्रतियोगी मौके, 2036 ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें विकसित करना, गवर्नेंस और नेतृत्व में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार स्किल्स, वॉलंटियरिंग के मौके और देश बनाने के रास्ते देना।

'ड्रग की समस्या से निपटने में खेलों की भूमिका'

पीएम मोदी ने कहा, जब हम 2036 ओलंपिक की बात करते हैं तो हमें अभी से खिलाड़ियों को तैयार करना होगा। कड़वी सच्चाई यह है कि अतीत में हमने ओलंपिक में शामिल होने वाली आधी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा नहीं लिया। जब मैं खेलों की बात करता हूं तो मेरा आशय केवल पदक जीतने से नहीं है। हमारे पैरा खिलाड़ी इस बात की मिसाल हैं कि खेल किस तरह जीवन बदल सकता है, मैं उनसे प्रेरित महसूस करता हूं। ड्रग की समस्या से निपटने में खेलों की बड़ी भूमिका है।

ओलंपिक में भागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर

पीएम ने युवा एथलीटों को संबोधित करते हुए कहा, 2036 ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार करने हैं। खिलाड़ियों की पहचान के लिए टैलेंट हब कार्यक्रम चलाना है। इसमें हर खेल में पदक आएं उसके लिए भारत को खेलों में महारत हासिल करनी होगी। मेडल टैली बढ़ाने के लिए हर खेल में आगे बढ़ना जरूरी। पांच से 15 साल के खिलाड़ियों की पहचान करनी होगी। खेल के लिए जो भी मदद चाहिए, सरकार उसमें समर्थन देगी। ओलंपिक में भागीदारी बढ़ाने पर जोर देना होगा। इसके लिए सरकार खिलाड़ियों को हर संभव मदद देगी।

सरकार की तरफ से दी जाएगी ट्रेनिंग

पीएम मोदी ने कहा, खेल को लेकर समाज का नजरिया बदला है। अच्छी खिलाड़ी बनने के लिए नशे से दूर रहना जरूरी है। मुझे भारत के युवाओं पर पूरा भरोसा है। कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है उसे पहचानें। स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की ओर से युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए अपने भाषण में पांच से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए देशव्यापी प्रतिभा खोज अभियान शुरू करने की घोषणा की थी जिससे कि ओलंपिक में भारत की भागीदारी बढ़ाई जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा, इस 15 अगस्त को मैंने लाल किले की प्राचीर से देश के लिए भारत के खेल संबंधी दृष्टिकोण को सामने रखा। यह विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है।

नेपाल बाढ़ में अभी भी 288 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने कहा- हम अधिकारियों से संपर्क में हैं

नई दिल्ली, एजेंसी। नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही के बाद भारत लगातार इस मामले में नजर बनाए हुए है। दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ताजा हालात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री ने कल नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की, गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत, नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव मदद का प्रस्ताव भी दिया। MEA प्रवक्ता ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद राहत और बचाव के काम जारी हैं। कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हालांकि, अभी भी 288 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।

MEA प्रवक्ता ने कहा कि लापता लोगों में 73 भारतीय नागरिक शामिल हैं जो त्रिशूली वन पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। काठमांडू में हमारा दूतावास इन लोगों के बारे में और जानकारी पाने के लिए प्रोजेक्ट हेड के संपर्क में है। नेपाल में बाढ़ की स्थिति के लिए विदेश मंत्रालय में एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल लोगों को लेकर बड़ा अपडेट

बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित नेपाल में कई लोगों के फंसे होने पर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पहला ग्रुप 73 लोगों का है जो त्रिशूली-1 पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके बाद, तमिलनाडु के नागरिकों के दो अलग-अलग ग्रुप हैं - एक में 37 और दूसरे में 49 लोग हैं - जिन्होंने सम्राट और फ्लाई एवरेस्ट ट्रैवल्स के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा की थी। रणधीर जायसवाल ने बताया कि पश्चिम बंगाल के 32 भारतीय नागरिकों का एक ग्रुप है जो सम्राट ट्रैवल्स की मदद से रसुवा जिले के तिमुरे गए थे।

मीडिया के जरिए फैसला नहीं दिया जा सकता... राजस्थान हाई कोर्ट के जज पर लगे आरोपों पर बोले सीजेआई सूर्य कांत

नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने कल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) संजीव प्रकाश शर्मा पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने चिंताओं पर ध्यान दिया है। पद पर मौजूद जज के खिलाफ ऐसे आरोपों से "स्थापित संस्थागत प्रक्रियाओं के जरिए सख्ती से" निपटा जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि कोई भी फैसला मीडिया के जरिए नहीं दिया जा सकता है। जस्टिस मेहता ने मुख्य न्यायाधीश को भेजे अपने 3 अलग-अलग पत्रों में जस्टिस शर्मा के कार्यकाल में गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं और चुनिंदा मामलों को लिस्ट करने यानी केस लिस्टिंग) का आरोप लगाया था। CJI सूर्य कांत, इस समय जर्मनी और इंग्लैंड की 4 दिन की यात्रा पर हैं, ने एक बयान जारी कर कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट के ACJ पर लगाए गए आरोपों को अंतिम परिणाम नहीं माना जा सकता। जज को भी अपना पक्ष रखने का उचित मौका दिया जाना चाहिए।

उचित विचार के बाद ही कोई फैसला : सीजेआई सूर्य

अपने बयान में सीजेआई ने कहा, "कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पद पर बनाए रखने, उनका ट्रांसफर करने या उनके खिलाफ कोई अन्य प्रशासनिक कार्रवाई करने का फैसला सक्षम संस्थागत प्राधिकरण की ओर से पूरे मामले पर उचित विचार करने के बाद लिया जाएगा।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जजों से जुड़ी निजी तौर पर की गई शिकायतों का निपटारा "मीडिया में एक-दूसरे के खिलाफ किए गए दावों" के जरिए नहीं होने दे सकता।

महज आरोप लगा देने से ही फैसला नहीं : सीजेआई

हालांकि, CJI ने कहा कि "पत्रों की सामग्री पर सार्वजनिक तौर पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता"। उन्होंने आगे कहा, "महज आरोप लगा दिए जाने से ही इसे जज के खिलाफ कोई फैसला नहीं माना जा सकता। मामले की जांच सही स्तर पर की जा रही है और इस प्रक्रिया में जस्टिस मेहता की ओर से दी गई जानकारी और जस्टिस शर्मा के जवाब, दोनों पर ध्यान दिया जाएगा।" जस्टिस मेहता ने मुख्य न्यायाधीश से राजस्थान हाई कोर्ट का प्रमुख बनाने के लिए किसी दूसरे राज्य से तुरंत एक चीफ जस्टिस नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पैसे वाले मुकमेबाजों को फायदा पहुंचाने के लिए केस लिस्टिंग में हेरफेर कर रहे हैं।

'दंगों के मास्टरमाइंड थे शरजील इमाम और उमर खालिद', हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को मास्टरमाइंड बताया है। अदालत में पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं का भी विरोध किया।

पिछली सुनवाई (31 जुलाई) में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल करने को कहा था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि शरजील इमाम और उमर खालिद दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड थे। पुलिस के पास इनके खिलाफ दंगों की योजना बनाने, लोगों को जुटाने और दंगों में रणनीतिक भूमिका निभाने से जुड़े अहम सबूत है।

दिल्ली दंगों में इनकी भूमिका अलग

दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि दोनों की नई जमानत याचिकाएं अपने आप में ही 'गैरकानूनी' और कोर्ट को गुमराह करने वाली हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सहआरोपियों को जमानत दे दी थी, लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम को यह कहते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया था कि दिल्ली दंगों में इनकी भूमिका अलग है।

नए सिरे से लगा सकते हैं जमानत याचिका

पुलिस ने यह भी जिक्र किया कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि इस केस में यूएपीए की धारा 43डी(5) लागू होती है, जिसमें जमानत की सख्त शर्तों का प्रावधान है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जनवरी के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते समय नए सिरे से जमानत के लिए दो शर्त लगाई थीं। पुलिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शरजील इस मामले में अहम गवाहों के बयान होने या फिर इस फैसले के एक साल पूरी होने पर नए सिरे से फिर जमानत की याचिकाएं लगा सकते है।पुलिस का कहना है कि अभी यह दोनों ही शर्त पूरी नहीं हुई है। लिहाजा इस स्तर पर दोनों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। बता दें कि यह मामला 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर हुए दंगों से जुड़ा है, जिनमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।

'पितृसत्ता खत्म करनी है तो वंदे मातरम पूरा गाइए'

बांसुरी स्वराज की राहुल गांधी को चुनौती, कांग्रेस नेता ने ऐसे दिया जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। राहुल गांधी के 'स्मैश द पैट्रियार्की' यानी पितृसत्ता को खत्म करने वाले बयान पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधा है। बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह सच में पितृसत्ता खत्म करना चाहते हैं तो पूरा वंदे मातरम गाकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि उन्हें क्रिसमस कैरल गाने में भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा वंदे मातरम गाने में भी वह सहज हैं और वह शिव तांडव का पाठ भी कर सकती हैं।

बांसुरी ने आगे कहा कि राहुल गांधी को भी 'वंदे मातरम' का पूरा गायन करके दिखाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद ने वंदे मातरम को 'जन गण मन' के समान सम्मान देने का फैसला किया है, लेकिन कांग्रेस इसे नहीं मानती। बांसुरी ने कांग्रेस पर मनुस्मृति की सोच की बात करने के बावजूद 'जिहादी माइंडसेट' के सामने झुकने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 'मादरे वतन' और भारत माता को देवी के रूप में दिखाने वाले वंदे मातरम के हिस्से को काटती है। सुप्रिया श्रीनेत ने बांसुरी स्वराज का वीडियो X पर शेयर कर इसी बात को लेकर सवाल उठाया।

कानून-व्यवस्था जीरो... अंकित बालियान की हत्या पर अखिलेश का हमला, संजीव बालियान बोले-भरे शहर में मार डाला, नहीं पहुंची पुलिस

आर्यावर्त क्रांति

लखनऊ। यूट्यूबर और हरियाणवी गायक अंकित बालियान की उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हत्या कर दी गई। उनपर अज्ञात हमलावरों ने जिम के बाहर ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा, "शामली में लोकप्रिय गायक अंकित बालियान की कई राउंड गोलियां चलाकर हत्या किए जाने से इलाके में भय का माहौल है। प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति जीरो पर पहुंच गई है।"

अखिलेश ने इस बालियान की हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस हत्या की जांच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के पहलू से भी की जानी चाहिए। सपा प्रमुख ने कहा, "बालियान की मां द्वारा सड़क पर बेटे के शव को गोद में लेकर शोक मनाने की घटना बेहद हृदयविदारक है। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाट समाज में आक्रोश है और पूरा जाट समुदाय इस घटना को अपने ऊपर हुए हमले के तौर पर देख रहा है।"

'मौके पर पुलिस नहीं पहुंची ये बहुत दुख की बात'

पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के बाद उनके घर पहुंचे। उन्होंने कहा, "एक ऐसा कलाकार जिसकी लोकप्रियता हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों जगह थी। जो सभी का प्यारा था, उसकी हत्या शाम के समय भरे शहर के बीच कर दी गई। इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है। मौके पर पुलिस नहीं पहुंची, कोई नहीं पहुंचा। बहुत दुख की बात है।"

अंकित बालियान के यूट्यूब चैनल पर 3।66 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो अपने वीडियो में विभिन्न कलाकारों और सहयोगियों के साथ नजर आते थे। उनके कई वीडियो में बंदूक, अन्य हथियारों और एसयूवी को भी दिखाया गया था। फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक, हमलावर दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे और उन्होंने बालियान पर कई राउंड फायरिंग की। घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं।

मोदी कैबिनेट में होगा विस्तार, युवा और महिलाओं को मिलेगा मौका ; 70+ उम्र के मंत्रियों पर क्या होगा फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। मोदी मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार में युवाओं और महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। सरकार मंत्रिमंडल को युवा चेहरा देने के साथ-साथ नए सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रियों की कुल संख्या बढ़ाकर करीब 75 करने और महिला मंत्रियों की संख्या मौजूदा सात से बढ़ाकर कम से कम 12 करने की योजना पर मंथन चल रहा है।

मंत्रिमंडल में 50 वर्ष से कम उम्र के मंत्रियों की हिस्सेदारी मौजूदा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर करीब 40 प्रतिशत किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया के दौरे से 2 सितंबर को लौटने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, संभावित विस्तार में नए सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व देने के साथ युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा आगामी चुनाव वाले राज्यों के राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

वर्तमान में मंत्रिमंडल में सात महिला मंत्री हैं। विस्तार के बाद इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 12 किए जाने की तैयारी है। वहीं, 50 वर्ष से कम उम्र के मंत्रियों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। फिलहाल 50 वर्ष से कम आयु के केवल 17 मंत्री हैं, जबकि 40 वर्ष से कम उम्र के महज दो राज्यमंत्री हैं।

आर्थिक आधार पर आरक्षण सहित 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। राष्ट्रीय सवर्ण परिषद ने गुरुवार को सामान्य समाज के हितों, सामाजिक समानता और विभिन्न नीतिगत मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पहले शहर के तिकोनिया पार्क में एकत्र होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। इसके बाद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिलाधिकारी के माध्यम से भारत की राष्ट्रपति को संबोधित पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया।

परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगों का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर, न्याय और सम्मान दिलाना है। संगठन ने मांग पत्र के माध्यम से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक अपनी आवाज पहुंचाते हुए मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की अपील की है। ज्ञापन में पहली प्रमुख मांग दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति से संबंधित रही। संगठन ने कहा कि नागरिकों और सामाजिक संगठनों को संविधान एवं कानून के दायरे में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने के लिए उचित अनुमति एवं व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। दूसरी मांग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व्यवस्था को समाप्त करने अथवा उसके प्रावधानों की व्यापक समीक्षा करने से जुड़ी रही। परिषद ने इस संबंध में कानून एवं संविधान की भावना के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। तीसरी और प्रमुख मांग आरक्षण व्यवस्था में व्यापक सुधार की रही। संगठन ने कहा कि आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति और वास्तविक आर्थिक कमजोरी को प्राथमिकता देकर तय किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो सके। चौथी मांग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कानूनों और नीतियों की निष्पक्ष एवं व्यापक समीक्षा की रही। परिषद का कहना है कि कानूनों के दुरुपयोग की संभावनाओं को रोकते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ न्याय और समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए। पांचवीं एवं अंतिम मांग सामान्य समाज के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कानून बनाए जाने की रही। संगठन ने आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के नागरिकों के अधिकारों, सम्मान और हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कानूनी एवं नीतिगत प्रावधान किए जाने की मांग की। ज्ञापन के अंत में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद ने विश्वास जताया कि लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की भावना के अनुरूप उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

ज्ञापन देने वालों में अयोध्या मंडल प्रभारी गौरी शंकर शर्मा, जिलाध्यक्ष सुल्तानपुर अमित उपाध्याय, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्य दुबे, संस्थापक एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी पंकज धवैया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आचार्य भरत तिवारी तथा जिलाध्यक्ष रायबरेली सुधीर तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बहन के घर जा रहा बाइक सवार घायल, मेडिकल रेफर, हालत गंभीर

आर्यावर्त संवाददाता

अलीगढ़। गंगीरी थाना अंतर्गत गुरुवार की सुबह करीब 8:30 बजे गांव बिलोना भट्ठा पर एक सड़क दुर्घटना हुई। इस हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

जिला कासगंज कोतवाली के गांव नगला क्लू निवासी भूपेन्द्र पुत्र राम निवास अपनी बहन के घर जा रहे थे। वह अपनी बहन को चावल देने के लिए नगला इंद्रा, थाना गंगीरी जा रहे थे। भूपेन्द्र अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी एक ओवरलोड बालू के ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे फंस गई। भूपेन्द्र को गंभीर चोटें आईं।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत घायल भूपेन्द्र को इलाज के लिए छर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। छर्रा सीएचसी से भूपेन्द्र को आगे के बेहतर इलाज के लिए जे एन मेडिकल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ओवरलोड बालू से लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

राजू दास के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग, मोस्ट ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। मोस्ट कल्याण संस्थान के बैनर तले मोस्ट ब्लॉक प्रमुख धनपतगंज रामाकांत यादव के नेतृत्व में राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में लिखा है कि बीते 24 अगस्त को लगभग दोपहर 12 बजे कुंवर निषाद अपने निवास से डी.डी. न्यूज पर आयोजित एक लाइव टीवी डिबेट में शामिल थे। उक्त लाइव टीवी डिबेट के दौरान अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास द्वारा निषाद समुदाय का होने के कारण बार-बार माँ को लेकर गाली सहित अत्यंत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी दी गई, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन है। मोस्ट कल्याण संस्थान ने मांग की है कि राजू दास के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जाय एवं राजू दास जैसे अधार्मिक कृत्य करने वाले को भगवा वस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ताकि भविष्य में धार्मिक वेशभूषा की आड़ में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मोस्ट निदेशक शिक्षक श्यामलाल निषाद गुरूजी ने योगी सरकार से माँग की है कि राजू दास जैसे दुष्टों पर तत्काल कठोर कार्यवाही कर सार्वजनिक जीवन से पाबंद किया जाय अन्यथा ये माना जाएगा कि योगी सरकार अपने पालतू गुंडों से निषादों को अपमानित करा रही है इस अपमान का बदला आगामी विधानसभा चुनाव में निषाद समाज अवश्य लेगा। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश कमेटी रज्जन प्रसाद, मोस्ट प्रमुख जीशान अहमद, जनरल सेक्रेटरी राम उजागिर यादव, अनिल कुमार सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे।

'तबादला काफी नहीं, संपत्ति की हो जांच', रवि गौतम का सात दिन से धरना जारी, महापंचायत का किया एलान

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मेरठ में कलेक्ट्रेट गेट पर हुए बवाल के आरोपी रवि गौतम का कमिश्नरी पार्क में धरना बुधवार को सातवें दिन भी जारी रहा। रवि गौतम ने 30 अगस्त को कमिश्नरी पर महापंचायत करने का एलान किया है।

उनका कहना है कि केवल आईपीएस अविनाश पांडेय का तबादला कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। उन्होंने अविनाश पांडेय और एसपी देहात अभिजीत कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

30 अगस्त को कमिश्नरी पर होगी महापंचायत

रवि गौतम ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर 30 अगस्त को कमिश्नरी पर ही महापंचायत की जाएगी। वह पिछले सात दिनों से कमिश्नरी पार्क में धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि ललिता गौतम मामले में पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

तबादले को बताया अधूरी कार्रवाई

रवि गौतम ने कहा कि तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय का तबादला पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। उन्होंने अविनाश पांडेय और एसपी देहात अभिजीत कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग की। साथ ही दोनों समेत पिटाई में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की।

ललिता गौतम मामले के विरोध से जुड़ा है विवाद

रोहटा थाना क्षेत्र में दलित छात्रा ललिता गौतम का शव मिलने के बाद परिजनों ने अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों ने आठ जुलाई को कलेक्ट्रेट गेट पर धरना-प्रदर्शन किया था। करीब तीन घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए लाठियां फटकारी थीं। इसी दौरान तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय के बंदी वाहन के अंदर रवि गौतम को कई थप्पड़ मारने का वीडियो सामाजिक माध्यम पर प्रसारित हुआ था। इसके बाद मामला काफी चर्चा में आया।

महापंचायत रोकने के लिए अधिकारियों ने बढ़ाई सक्रियता

महापंचायत के एलान के बाद पुलिस अधिकारी इसे रोकने के प्रयास में जुट गए हैं। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि रवि गौतम की ओर से महापंचायत का एलान किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस समाज के सभी लोगों के संपर्क में है, ताकि महापंचायत न हो।

सात दिन से जारी है धरना

रवि गौतम का कहना है कि जब तक मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होती, उनका धरना जारी रहेगा। उनकी प्रमुख मांगों में संबंधित पुलिस अधिकारियों पर प्राथमिकी, संपत्ति की जांच और कथित पिटाई के मामले में कार्रवाई शामिल है।

सुल्तानपुर में राजस्व का बड़ा खेल उजागर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिले की सदर तहसील से जमीन के फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परगना मीरानपुर के मौजा नकराही की गाटा संख्या-84 की जमीन को लेकर कागजात में ऐसी हेराफेरी का आरोप लगा है कि मृतक का नाम आज भी खतौनी में जिंदा है।

पीड़ति शांती मिश्रा पत्नी रामकुमार मिश्रा, निवासिनी विनोवापुरी (लोलेपुर) ने श्रीमान तहसीलदार सदर को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि उन्होंने उक्त गाटा संख्या-84 रकबा 0.4600 हे. में से 1ध्2 हिस्सा यानि 0.2300 हे. का बैनामा श्रीमती कमरजहाँ पुत्री रईसुल जमा पत्नी इशितयाक अहमद से विभिन्न तिथियों पर लिया था। प्रार्थिनी का आरोप है कि बैनामे के बाद गाटा संख्या-84 में कमरजहाँ का कोई हिस्सा व हक नहीं बचा। लेकिन कागजात की गलती से कमरजहाँ के वारिसान का नाम उनकी मृत्यु के बाद भी खतौनी में दर्ज हो गया। आरोप है कि इसी गलती का फायदा उठाते हुए कमरजहाँ के वारिस जियाउद्दीन पुत्र इशितयाक अहमद ने फर्जी तरीके से यह जमीन मोहम्मद शेरुद्दीन हाशमी पुत्र मोइनुद्दीन निवासी ग्राम भुलकी के हक में बैनामा कर दिया, जबकि उक्त खाते में जियाउद्दीन की कहीं कोई जमीन ही नहीं है। पीड़ति ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि इसी फर्जी बैनामे के चलते आये दिन झगड़ा-झंझट हो रहा है और किसी भी दिन फौजदारी की नौबत आ सकती है। पीड़ति ने तहसीलदार महोदय से मांग की है कि तत्काल मौजा नकराही, गाटा संख्या-84 में हुई कागजात की गलती को दुरुस्त कर कमरजहाँ व उनके वारिसान का नाम काटा जाए और फर्जी बैनामा करने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया जाए, ताकि बड़ी घटना को रोका जा सके।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौत का सफर

खड़ी बस में ट्रक ने मारी टक्कर, तीन की मौत, 11 घायल

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गुरुवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और वाहन चालकों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए। बल्दीराय थाना क्षेत्र में रामनगर गदियाने के पास माइल स्टोन 96.6 पर सुबह करीब 5रू20 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने किनारे खड़ी डबल डेकर बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस सवार तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक डबल डेकर निजी बस संख्या यूपी 63 एटी 4188 दिल्ली से यात्रियों को लेकर बिहार जा रही थी। बताया गया कि चालक शिवम सिंह को नींद आने के कारण बस को एक्सप्रेसवे के किनारे खड़ा किया गया था और वह सहचालक कमलेश को वाहन की जिम्मेदारी देने की तैयारी में था। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक संख्या बीआर 02 जीडी 6496 ने खड़ी बस में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार श्याम लाल मंडल (28), बिनोद मंडल (50) और किरण देवी (48) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से निकल गया और करीब चार किलोमीटर दूर उसे खड़ा कर फरार हो गया।

घटना की सूचना यूपीडा कंट्रोल को 5.23 बजे तथा डायल-112 को करीब 5.50 बजे दी गई। सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी प्रभात सिंह, नायब तहसीलदार गुलाब सिंह, स्थानीय पुलिस और यूपीडा की टीम एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची। राहत-बचाव अभियान चलाकर घायलों को सीएचसी तथा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और परिजनों को सूचना दे दी गई है। दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे की जांच जारी है।

तीन दिन बाद नहर में मिला बीएससी छात्रा का शव

सुल्तानपुर। बल्दीराय थाना क्षेत्र में तीन दिन से लापता चल रही 20 वर्षीय बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा महक पाल का शव गुरुवार सुबह नहर में उतराता मिलने से हड़कंप मच गया। छात्रा के नहर में कूदने के बाद से ही पुलिस और गोताखोर उसकी तलाश में जुटे हुए थे। जानकारी के मुताबिक महक पाल ने बल्दीराय थाना क्षेत्र के मथाना पुल से नहर में छलांग लगाई थी। घटना के बाद बल्दीराय पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर में व्यापक तलाश अभियान चलाया लेकिन तीन दिनों तक छात्रा का कोई सुराग नहीं मिल सका। गुरुवार सुबह धनपतगंज थाना क्षेत्र के हरौरा बाजार में नहर पुलिया के पास स्थानीय लोगों ने पानी में एक शव उतराता देखा। सूचना मिलते ही धनपतगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकलवाया। मौके पर पहुंचे छात्रा के भाई पियूष ने शव की पहचान अपनी बहन महक पाल के रूप में की। शव की पहचान होते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 60 करोड़ की हेराफेरी, ID हैक कर 3 .18 लाख अपात्र बनाए लाभार्थी

आर्यावर्त संवाददाता

प्रतापगढ़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सेंध लगाए जाने की जांच में तेजी आई है। बुधवार को इस प्रकरण में साइबर थाने में एक अज्ञात आरोपित पर 60 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी का केस दर्ज किया गया। पुलिस को तीन लाख से अधिक अपात्रों के नाम की सूची भी सौंपी गई है। अब गलत ढंग से सरकारी पैसा हजम करने व उनको इसका लाभ देकर अपनी जेब भरने वालों पर कार्रवाई होगी।

चार साल पहले कुंडा तहसील में योजना की लागिन, आइडी का दुरुपयोग करके सरकारी पोर्टल के विकल्प डायरेक्ट एंट्री के जरिए जालसाजों ने बड़े पैमाने पर खेल किया था। इसमें नाबालिग और अन्य अपात्रों का पंजीकरण इस सरकारी योजना में करवा दिया गया था। यही नहीं इसमें कई दूसरे जिले और प्रांत के लोग भी शामिल थे।

योजना के डायरेक्ट एंट्री का विकल्प में सेंध लगाई

पहले पीएम किसान पंजीकरण तहसील से अग्रसारित होकर जनपद कार्यालय की लागिन पर प्राप्त होता था। चार साल पहले कृषकों की सुविधा के लिए सरकार ने तहसीलों पर डायरेक्ट एंट्री का विकल्प उपलब्ध कराया दिया था। इसी में शातिरों ने सेंध लगाई।

गडबड़ी पकड़ी गई तो हुई सख्ती

इसकी जांच तहसील प्रशासन से लेकर विजिलेंस तक ने की। बाद में शासन स्तर पर जांच होने व गड़बड़ी की पुष्टि होने पर सख्ती शुरू हुई। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने इस गंभीर प्रकरण में आरोपितों पर एफआइआर दर्ज करने को कहा। एसपी को पत्र भी लिखा था।

उप कृषि निदेशक ने केस दर्ज कराया था

उप कृषि निदेशक अश्वनी कुमार सिंह द्वारा दर्ज कराए गए केस में कहा गया है कि अब तक 60 करोड़ रुपये से अधिक के दुरुपयोग की आशंका है। इसमें कई लोग शामिल हैं। पुलिस को 318846 अपात्रों की सूची पेन ड्राइव में सौंपी गई है। एएसपी आलोक कुमार का कहना है कि कृषि विभाग की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। संबंधित अभिलेखों की जांच करके कार्रवाई की जाएगी।

कानपुर की धंसी सड़क का खौफनाक मंजर, वाटरफॉल नहीं... जमीन के नीचे दिखा मौत का सैलाब

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। कानपुर में तेज बारिश के बीच जाजमऊ इलाके में सड़क धंसने से हड़कंप मच गया। सरिया चौराहे के पास जाजमऊ से वीआईपी सर्किट हाउस जाने वाली सड़क अचानक धंस गई और कुछ ही देर में यहां करीब 3 मीटर चौड़ा और 18 फीट गहरा गड्ढा बन गया। सड़क में बने इस विशाल गड्ढे में बारिश का पानी तेजी से भरने लगा, जबकि आसपास जमा पानी भी इसी में समाने लगा। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

घटना उस समय हुई जब क्षेत्र में तेज बारिश हो रही थी। करीब 11 बजे सरिया चौराहे के पास सड़क अचानक धंसने लगी। शुरुआत में सड़क का एक छोटा हिस्सा नीचे गया, लेकिन कुछ ही देर में इसका दायरा बढ़ता चला गया। सड़क धंसने के बाद करीब 3 मीटर चौड़ा और 18 फीट गहरा गड्ढा बन गया।

गड्ढा इतना गहरा था कि आसपास मौजूद लोगों के बीच दहशत फैल गई। बारिश का पानी तेजी से इसमें गिर रहा था। आसपास की सड़कों पर जमा पानी भी बहकर इसी गड्ढे में पहुंचने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने इस नजारे का वीडियो बनाना शुरू कर दिया।

पहले भी बन चुका था गड्ढा

स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जगह सड़क धंसी है, वहां करीब एक महीने पहले भी छोटा गड्ढा हुआ था। लोगों के मुताबिक, उस समय संबंधित विभाग ने गड्ढे में मलबा भरवाकर सड़क को दुरुस्त कर दिया था। हालांकि, अब उसी स्थान पर सड़क का बड़ा हिस्सा धंस जाने के बाद निर्माण और मरम्मत की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर पहले बने गड्ढे की गंभीरता से जांच कराकर सड़क की मजबूती सुनिश्चित की जाती, तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। फिलहाल इतने बड़े गड्ढे के कारण आसपास रहने वाले लोगों में भी डर का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए सड़क पर यातायात को एक तरफ से संचालित कराया गया। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। सड़क धंसने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। भारी बारिश के कारण जमीन के भीतर पानी का दबाव बढ़ने, सड़क के नीचे की मिट्टी खिसकने या किसी अन्य तकनीकी वजह की आशंका जताई जा रही है। वास्तविक कारण जांच के बाद ही सामने आएगा।

वीआईपी रूट पर सड़क धंसने से सवाल

जिस सड़क पर यह विशाल गड्ढा बना है, वह जाजमऊ से वीआईपी सर्किट हाउस की ओर जाने वाले मार्ग से जुड़ी है। ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग पर सड़क का इस तरह धंस जाना नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

कलाई पर बंधता धागा, दिलों में जगाता है रिश्तों का विश्वास

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। रक्षाबन्धन नाम लेते ही आंखों के सामने बहन का स्नेह, भाई की कलाई और उस पर बंधा प्रेम का पवित्र धागा उभर आता है। यह पर्व महज राखी बांधने और उपहार देने की रस्म नहीं, बल्कि भाई-बहन के उस रिश्ते का उत्सव है, जिसमें बचपन की शरारतें, रूठना-मनाना, सुख-दुःख की साझेदारी और जीवनभर साथ निभाने का विश्वास समाया होता है। सावन की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबन्धन भारतीय संस्कृति में प्रेम, सुरक्षा, त्याग और पारिवारिक संस्कारों का अनूठा पर्व है। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसके पीछे केवल रक्षा की अपेक्षा नहीं, बल्कि भाई के सुखी, स्वस्थ और उज्ज्वल जीवन की प्रार्थना भी होती है। भाई के लिए यह धागा एक वचन बन जाता है कि जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में वह अपनी बहन के सम्मान, अधिकार और खुशियों के लिए उसके साथ खड़ा रहेगा। यही कारण है कि राखी का धागा छोटा होकर भी भावनाओं में बहुत बड़ा होता है। भारतीय परंपरा में रक्षासूत्र को मंगल और रक्षा का प्रतीक माना गया है। धार्मिक परंपराओं में रक्षा-सूत्र बांधने की विधि का उल्लेख मिलता है और कालांतर में यही परंपरा भाई-बहन के स्नेह से विशेष रूप से जुड़ गई। रक्षाबन्धन परिवार को जोड़ने के साथ समाज में प्रेम, विश्वास और भाईचारे की भावना को भी मजबूत करता है। रक्षाबन्धन से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं लोकमानस में प्रचलित हैं। भगवान श्रीकृष्ण और द्रौपदी का प्रसंग तथा राजा बलि और माता लक्ष्मी से जुड़ी कथा रक्षाबन्धन के भावनात्मक और धार्मिक महत्व को रेखांकित करती है। इन कथाओं का मूल संदेश यही है कि रक्षा का संबंध केवल रक्त के रिश्ते से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और आत्मीयता से भी होता है। इतिहास और लोकपरंपराओं में राखी को सम्मान, संरक्षण और संबंधों की निशानी के रूप में देखा गया है। राजपूत परंपरा में राखी के माध्यम से भाईचारे और रक्षा-संकल्प की भावना के उदाहरण मिलते हैं। समय के साथ यह पर्व सामाजिक सद्भाव और पारस्परिक सम्मान का प्रतीक भी बन गया। हिंदी साहित्य ने भी रक्षाबन्धन की भावनाओं को अत्यंत मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। राष्ट्रकवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना 'राखी' में बहन का स्नेह और विरह अत्यंत मार्मिक रूप में दिखाई देता है-

"मैं हूँ बहिन, किंतु भाई नहीं है,
है राखी सजी पर कलाई नहीं है।"

मुख्यमंत्री योगी ने स्टार्टअप और नवाचार क्षेत्र के उद्यमियों को किया सम्मानित

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास में सहभागी उद्यमियों को सम्मानित किया। उन्होंने भारत इनोवेट्स में हिस्सा लेने वाले उद्यमियों को सम्मानित करने के साथ स्टार्टअप प्रोत्साहन एवं इन्क्यूबेटर्स प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इन्क्यूबेटर मान्यता प्रमाण पत्र तथा यूपी स्टार्टअप फंड समर्थित स्टार्टअप्स को भी सम्मानित किया।मुख्यमंत्री ने मंच पर पांच स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान किए। इनमें सिंह डायनमिक प्राइवेट लिमिटेड की अनुषी वर्मा, डिकोड सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड की रिया कुमारी वंशगोपाल, त्रिशूल स्पेस के दिव्यम, जीनोमिकी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की डॉ. दीक्षा भारती तथा पीएचएसआई टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के तुषार राज शामिल रहे।इन्क्यूबेटर्स प्रोत्साहन राशि के चेक भी वितरित किए गए। इस अवसर पर नवयुग नवाचार फाउंडेशन, आईईटी लखनऊ के डॉ. पुष्कर तथा एनआईईटी के डॉ. संजय कुमार को एंड इनोवेशन, जौनपुर के राकेश सिंह और अविनाश तथा एमएसयू एकेडमिक फाउंडेशन, सहारनपुर की डॉ. विमला वाई और अभिनव पुंडीर को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।यूपी स्टार्टअप फंड समर्थित स्टार्टअप्स को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री ने मैग्नम टेक्नोलॉजी के तरुण सेनानी, अल्फाड्रायड इंडिया के अक्षत राज और गौरव जोशी को सम्मानित किया। वहीं ब्रिस्क ओलिफ के सुनील प्रेमजी को लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किया गया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत इनोवेट्स में हिस्सा लेने वाले उद्यमियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने अननंत सिस्टम्स, एंड्योर एयरसिस्टम्स, सूयो मैन्युफेक्चरिंग, राफे तथा वर्वेसमी मिक्स्ड सिग्नल के प्रतिनिधियों को मंच पर सम्मानित किया गया।मुख्यमंत्री ने इन्क्यूबेटर मान्यता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। वीबीएसपीयू इन्क्यूबेशन सम्मानित किया।

शहीद पथ किनारे लड़ाई-झगड़े के दौरान युवक के पास से अवैध पिस्टल और चार कारतूस बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार थाना पुलिस ने शहीद पथ के किनारे लड़ाई-झगड़ा कर रहे पांच लोगों में से एक युवक को अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से .32 बोर की एक अवैध पिस्टल, एक मैगजीन और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार थाना गोमतीनगर विस्तार की टीम 27 अगस्त की रात सेक्टर-1 में गश्त, वांछित अपराधियों की तलाश, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग कर रही थी। पुलिस टीम जनेश्वर गेट नंबर-7 पर मौजूद थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि शहीद पथ के किनारे सीएमएस तिराहे से पहले चार-पांच लोग आपस में लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं।सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां शहीद पथ के किनारे पांच व्यक्ति सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार सड़क पर खड़ी कर आपस में विवाद करते मिले। पुलिस ने सभी को रोककर उनके नाम-पते पूछे और तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक युवक के कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुआ।पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान विवेक कुमार चौहान पुत्र राम करन चौहान, निवासी मकान नंबर 27, सदरपुर करौरा, थाना गोसाईगंज, लखनऊ, उम्र करीब 28 वर्ष के रूप में हुई। उसके कब्जे से .32 बोर की एक अवैध पिस्टल, एक मैगजीन तथा चार जिंदा कारतूस बरामद हुए।पुलिस टीम ने मौके पर ही बरामदगी की कार्रवाई पूरी की। इसके बाद उपनिरीक्षक उपेन्द्र गिरि की तहरीर के आधार पर थाना गोमतीनगर विस्तार में मुकदमा संख्या 155/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत विवेक कुमार चौहान के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।पुलिस ने बताया कि आरोपी को 27 अगस्त को शहीद पथ के किनारे सीएमएस तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक उपेन्द्र गिरि, उपनिरीक्षक संदीप कुमार, उपनिरीक्षक राजेन्द्र तिवारी, उपनिरीक्षक उमंग कसौधन, उपनिरीक्षक अंकित कुमार, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार यादव तथा कांस्टेबल अनुराग यादव शामिल रहे।

संक्षेप

जलभराव, सफाई और संक्रामक रोगों की रोकथाम को लेकर ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अपने प्रभार वाले जनपद भदोही में कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और जनसुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। बारिश के मौसम को देखते हुए उन्होंने जलभराव, साफ-सफाई, संक्रामक रोगों की रोकथाम और पेयजल व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को मौके पर जाकर व्यवस्थाओं की निगरानी करनी होगी।नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि किसी भी नगरीय क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जहां जलभराव की समस्या सामने आ रही है, वहां तत्काल जल निकासी की व्यवस्था कराते हुए स्थायी समाधान की दिशा में कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान जलजमाव के कारण मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर वहां नियमित रूप से एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जाए।साफ-सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए ए.के. शर्मा ने कहा कि शहरों में कहीं भी कूड़े का ढेर दिखाई नहीं देना चाहिए। नियमित कूड़ा उठान और उसके समुचित निस्तारण के साथ सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, प्रमुख मार्गों और आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सफाई कार्य केवल कागजों तक सीमित न रहे।

इटौंजा में महिला ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

लखनऊ। थाना इटौंजा क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर खेड़ा में गुरुवार सुबह एक महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली।पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान कलावती पत्नी कल्लू, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम अहमदपुर खेड़ा, थाना इटौंजा, लखनऊ के रूप में हुई है। बताया गया कि महिला ने अपने घर में दुपट्टे का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लिया और परिजनों की मौजूदगी में पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जानकारी जुटा रही है। मामले में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यूपीआरएलएम के इन्क्यूबेशन कार्यक्रम को केंद्र की मंजूरी

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'लखपति दीदी' के संकल्प को साकार करने की दिशा में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल को बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा तैयार इन्क्यूबेशन कार्यक्रम को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मंजूरी प्रदान कर दी है।उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस कार्यक्रम से प्रदेश की ग्रामीण महिला उद्यमिता को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ के एंटरप्राइज इन्क्यूबेशन सेंटर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का सहयोग ग्रामीण महिला उद्यमियों को विशेषज्ञता, व्यावसायिक अनुशासन और बाजार की समझ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।उन्होंने कहा कि यह पहल उत्तर प्रदेश को महिला उद्यमिता के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इसे प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया।कार्यक्रम के तहत प्रदेशभर से करीब 150 महिला उद्यमों को आईआईएम लखनऊ द्वारा 18 महीने तक संरचित इन्क्यूबेशन सहयोग प्रदान किया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले महिला उद्यमों को अनुदान के साथ शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इससे ग्रामीण महिलाओं को अपने कौशल और उत्पादों को व्यावसायिक अवसरों में बदलने में मदद मिलेगी।राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार ने बताया कि इच्छुक महिला उद्यमी अपने निकटतम ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई, ग्राम संगठन या क्लस्टर स्तरीय संघ से संपर्क कर आवेदन कर सकती हैं।

रक्षाबंधन स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के अटूट बंधन का पर्व: नरेंद्र कश्यप

लखनऊ। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने भाई-बहन के असीम प्रेम, अटूट विश्वास और समर्पण के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।अपने शुभकामना संदेश में नरेंद्र कश्यप ने कहा कि रक्षाबंधन का पावन पर्व भारतीय संस्कृति की उस अद्भुत परंपरा का उत्सव है, जो स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के अटूट बंधन को दर्शाती है। यह पर्व भाई-बहन के रिश्ते की गरिमा को मजबूत करने के साथ ही परिवार और समाज में आपसी स्नेह, सम्मान एवं आत्मीयता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।राज्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के प्रेम का पर्व ही नहीं, बल्कि समाज में पारस्परिक विश्वास, जिम्मेदारी और सुरक्षा की भावना को मजबूत करने का भी संदेश देता है। इस पावन अवसर पर हम सभी को नारी सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहने का संकल्प लेना चाहिए।उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर समाज में समरसता, एकता और भाईचारे की भावना को और मजबूत करने का संकल्प लें। आपसी सहयोग और सद्भाव के माध्यम से ही एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण किया जा सकता है।नरेंद्र कश्यप ने कहा कि भारतीय संस्कृति के पर्व हमें प्रेम, सद्भाव और सामाजिक एकता का संदेश देते हैं। रक्षाबंधन भी इसी भावना को आगे बढ़ाने वाला पवित्र पर्व है, जो रिश्तों की मजबूती के साथ समाज में परस्पर सम्मान और विश्वास को बढ़ावा देता है।उन्होंने कामना की कि रक्षाबंधन का यह पावन एवं पुनीत पर्व सभी के जीवन में प्रेम, सद्भाव, समृद्धि और सौहार्द की वृद्धि करे तथा प्रदेश एवं देशवासियों के जीवन में सुख-शांति और खुशहाली लेकर आए।

महापौर सुषमा खर्कवाल ने सैन्य अधिकारियों को बांधी राखी, राष्ट्रसेवा के प्रति जताया सम्मान और कृतज्ञता

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर महापौर सुषमा खर्कवाल ने मध्य उत्तर प्रदेश सब एरिया मुख्यालय पहुंचकर जीओसी मेजर जनरल मनीष कुकरेती एवं अन्य सैन्य अधिकारियों को राखी बांधी और उनके साथ आत्मीयता से रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान उन्होंने देश की सुरक्षा में तैनात सैन्य अधिकारियों के प्रति सम्मान, स्नेह और कृतज्ञता व्यक्त की।इस अवसर पर पूर्व कार्यकारिणी उपाध्यक्ष एवं पार्षद चरनजीत गांधी, पार्षद गौरी सांवरिया, रीता राय, रश्मि सिंह, रेखा सिंह तथा पूर्व पार्षद कैंट एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष रंजिता शर्मा भी उपस्थित रहीं। सभी ने सैन्य अधिकारियों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं।रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान माहौल भावुक और आत्मीय रहा। महापौर ने कहा कि भारतीय सेना के जवान और अधिकारी अपने परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा का दायित्व निभाते हैं। ऐसे वीर सैनिकों के साथ रक्षाबंधन मनाना उनके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले सैन्यकर्मियों के साहस, त्याग और समर्पण के कारण ही देशवासी स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं।उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का पवित्र धागा केवल भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों और देशवासियों के बीच विश्वास, सम्मान और अपनत्व के रिश्ते को भी मजबूत करता है। सैन्य अधिकारियों की कलाई पर राखी बांधते हुए उपस्थित लोगों ने राष्ट्रसेवा के प्रति उनके समर्पण को नमन किया।महापौर ने सैन्य अधिकारियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय सेना के वीर जवानों का पराक्रम, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के इस आयोजन ने भाई-बहन के पारंपरिक स्नेह के साथ राष्ट्र और सैनिकों के बीच भावनात्मक संबंध को भी मजबूती प्रदान की।

किसान पथ सर्विस रोड पर वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, चालक-परिचालक हिरासत में

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बीकेटी थाना क्षेत्र में इंदौराबाग मोड़ के पास किसान पथ सर्विस रोड पर सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति की वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही बीकेटी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल वाहन को कब्जे में लेकर चालक और परिचालक को हिरासत में ले लिया है।पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अनिल पुत्र संतलाल, निवासी ग्राम शेरपुरा, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के रूप में हुई है। अनिल मड़ियांव क्षेत्र में काम करने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। इसी दौरान उनकी अपने भतीजे अंकित से मोबाइल फोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान दोनों ने इंदौराबाग मोड़ पर मिलने और वहां से साथ घर जाने की बात तय की थी।बताया गया कि अनिल इंदौराबाग मोड़ पर पहुंचने के बाद सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान किसान पथ सर्विस रोड की ओर से आ रहे वाहन संख्या जेके22सी5907 की चपेट में आ गए। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।हादसे की जानकारी मिलते ही थाना बीकेटी पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने आमजन की सहायता से घायल अनिल को उपचार के लिए रामसागर मिश्र 100 शैय्या चिकित्सालय, बीकेटी, लखनऊ पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने दुर्घटना में शामिल वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन जम्मू-कश्मीर से कोलकाता की ओर जा रहा था।

भारतीय चित्रकला में काव्य, प्रेम और विरह की भावाभिव्यक्ति पर ज्ञानवर्धक व्याख्यान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ द्वारा आयोजित 'पुरातत्व अभिरुचि पाठ्यक्रम-2026' के अंतर्गत कल डॉ. विजय माथुर, सलाहकार, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ने 'भारतीय चित्रकला में काव्य, प्रेम एवं विरह' विषय पर ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। उन्होंने भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों में विकसित चित्रकला परंपराओं के माध्यम से काव्य, प्रेम, मिलन और विरह की भावपूर्ण अभिव्यक्ति पर विस्तार से प्रकाश डाला।डॉ. विजय माथुर ने कहा कि भारतीय चित्रकला केवल रंगों और रेखाओं की कला नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की साहित्यिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक चेतना का सशक्त दृश्य माध्यम है। भारतीय सौंदर्यशास्त्र में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों ने चित्रकला को समृद्ध किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय चित्रकला में प्रेम और विरह केवल मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सौंदर्यपरक चेतना के महत्वपूर्ण आयाम भी हैं।उन्होंने कहा कि भारतीय कलाकारों ने काव्य में निहित सूक्ष्म भावनाओं को रंग, रेखा और प्रतीकों के माध्यम से सजीव बनाकर चित्रकला को विशिष्ट दृश्य-काव्य का स्वरूप प्रदान किया। भारतीय चित्रकला की विभिन्न परंपराओं में मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति निरंतर विकसित होती रही है।व्याख्यान के दौरान डॉ. माथुर ने अजंता की भित्ति चित्रकला से लेकर मध्यकालीन चित्रकला तक मानवीय भावनाओं की विकसित होती अभिव्यक्ति का उल्लेख किया।

पेट्रोल भरवाने के बाद भुगतान से किया इनकार, कर्मचारियों से मारपीट और गाली-गलौज करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। सरोजनीनगर थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली-गलौज करने और पेट्रोल का भुगतान किए बिना विवाद करने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन भी बरामद किया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।पुलिस के अनुसार पुलिस आयुक्त लखनऊ तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मो. मुश्ताक के निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त रल्लापल्ली वसंथ कुमार के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर अभिषेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक सरोजनीनगर राजदेव प्रजापति के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।मामला कानपुर रोड स्थित अश्विन ऊर्जा एचपी पेट्रोल पंप से जुड़ा है। पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक 23 अगस्त 2026 को स्कॉर्पियो सवार तीन अज्ञात लोग और उनके कुछ साथी पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। वाहन में पेट्रोल भरवाने के बाद जब कर्मचारियों ने भुगतान के लिए कहा तो आरोपियों ने कथित रूप से भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। घटना के बाद आरोपी मौके से चले गए।पेट्रोल पंप के मैनेजर चन्द्रमणि पुत्र योगेन्द्र कुंवर ने 27 अगस्त को थाना सरोजनीनगर में लिखित तहरीर देकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा संख्या 329/26 दर्ज किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 115(2), 352 एवं 351(3) के तहत स्कॉर्पियो सवार तीन लोगों तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटना के शीघ्र खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों को सक्रिय किया। पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करने के साथ तकनीकी और मैनुअल माध्यमों तथा स्थानीय सूचना तंत्र की मदद ली। जांच के दौरान पुलिस को अभियुक्त के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसके आधार पर अर्जुनगंज निवासी इशांत सिंह सेंगर पुत्र सिरीस कुमार सेंगर को गिरफ्तार किया गया।पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त की उम्र करीब 30 वर्ष है। उसे 27 अगस्त को गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बीबीएयू के 11वें दीक्षांत समारोह की रिहर्सल आयोजित, तैयारियों को दिया अंतिम रूप

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के 11वें दीक्षांत समारोह-2026 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इसी क्रम में गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में दीक्षांत समारोह की रिहर्सल आयोजित की गई। रिहर्सल की अध्यक्षता कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने की। उन्होंने समारोह से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण करते हुए कार्यक्रम को सफल और गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।रिहर्सल के दौरान दीक्षांत समारोह में अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं का विस्तृत अभ्यास कराया गया। विद्यार्थियों ने उत्साह और अनुशासन के साथ इसमें प्रतिभाग किया। इस दौरान विद्यार्थियों के प्रवेश एवं निकास, बैठने की व्यवस्था, मंचीय कार्यक्रम, उपाधि एवं पदक वितरण, अनुशासन, प्रोटोकॉल तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह 29 अगस्त 2026 को आयोजित होगा। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह दीक्षांत समारोह विशेष रूप से वर्ष 2023, 2024, 2025 एवं 2026 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जा रहा है।रिहर्सल के दौरान कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल, कुलसचिव डॉ. अश्विनी कुमार सिंह एवं सीओई प्रो. विक्रम सिंह यादव ने विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। विद्यार्थियों को निर्धारित स्थान पर बैठने, अनुशासित तरीके से मंच तक पहुंचने, उपाधि एवं पदक प्राप्त करने तथा निर्धारित मार्ग से वापस अपने स्थान पर आने की प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया। मंच संचालन और समारोह के विभिन्न चरणों के बीच समन्वय को भी परखा गया।कुलपति ने संबंधित अधिकारियों एवं आयोजन टीमों को निर्देश दिए कि समारोह में शामिल होने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों, अतिथियों और अन्य प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने सभी व्यवस्थाएं निर्धारित प्रोटोकॉल और समय-सीमा के अनुरूप सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।दीक्षांत समारोह में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उपाधियां प्रदान की जाएंगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं अन्य सम्मान से भी नवाजा जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन समारोह की गरिमा और भव्यता को ध्यान में रखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है।विश्वविद्यालय प्रशासन का उद्देश्य है कि बीबीएयू का 11वां दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का गौरवपूर्ण उत्सव बनने के साथ विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुशासन और गरिमा को भी प्रदर्शित करे।

बीबीएयू की दीवार से रेलिंग चोरी कर ऑटो में ले जाते आरोपी को रंगेहाथ पकड़ा, गिरफ्तार

लखनऊ। आशियाना थाना पुलिस ने बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की दीवार पर लगी रेलिंग चोरी कर ऑटो रिक्शा में लादकर ले जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी को विश्वविद्यालय के वरिष्ठ सुरक्षा पर्यवेक्षक ने चोरी का सामान ले जाते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया था और उसे पुलिस के सुपुर्द किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई रेलिंग और घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा बरामद किया है।पुलिस के अनुसार बीबीएयू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ सुरक्षा पर्यवेक्षक विजय बहादुर सिंह ने 26 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे एक व्यक्ति को विश्वविद्यालय की दीवार पर लगी रेलिंग चोरी कर ऑटो रिक्शा में लादकर ले जाते हुए पकड़ लिया। उन्होंने आरोपी को मौके से पकड़कर थाना आशियाना पुलिस के सुपुर्द किया और घटना के संबंध में लिखित तहरीर दी।

धान की फसल में कीट प्रकोप से बचाव के लिए किसान रहें सतर्क

धान की फसल में तना छेदक एवं पत्ती मोड़क कीट के प्रकोप को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क रहने और फसल की नियमित निगरानी करने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि कीटों के शुरुआती लक्षणों की समय पर पहचान कर उचित नियंत्रण उपाय अपनाने से फसल को होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। खेतों में आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का उपयोग तथा लंबे समय तक अधिक जलभराव रहने से इन कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए किसान संतुलित उर्वरक उपयोग और उचित जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें।

तना छेदक धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों में शामिल है। प्रारंभिक अवस्था में इसके प्रकोप की पहचान करना आसान है। प्रभावित पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पौधे के तने के निचले हिस्से में छोटे-छोटे छेद दिखाई देते हैं तथा मुख्य तना अंदर से खोखला हो जाता है।

तना छेदक का प्रकोप बढ़ने पर धान की बालियां सफेद होकर पूरी तरह सूख जाती हैं। इससे पौधे में दाने बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और उत्पादन में कमी आ सकती है। इसलिए खेत में यदि कुछ पौधों की पत्तियां अचानक पीली पड़ती दिखाई दें या तने में छेद नजर आएं, तो किसान तुरंत फसल का निरीक्षण कर आवश्यक नियंत्रण उपाय अपनाएं।

तना छेदक के नियंत्रण के लिए अनुशंसित छिड़काव

कृषि विभाग ने तना छेदक की रोकथाम के लिए क्लोरोसाइपर (क्लोरपाइरीफास 50 प्रतिशत + साइपरमेथ्रिन 5 प्रतिशत) का 50 मिलीलीटर प्रति स्प्रेयर की दर से छिड़काव करने की सलाह दी है।

धान की फसल में पत्ती मोड़क कीट भी नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे 'सांवा कीट' के नाम से भी जाना जाता है। इस कीट की हरी इल्ली धान की पत्तियों को मोड़कर उनके अंदर छिप जाती है और पत्तियों के हरे भाग को खाती है।

पत्ती मोड़क कीट के प्रकोप के बाद पत्तियों पर सफेद एवं पारदर्शी धारियां दिखाई देने लगती हैं। पत्तियों का हरा भाग नष्ट होने से पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्षमता प्रभावित होती है। खेत में ऐसी पत्तियां दिखाई देने पर किसान फसल का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें और शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण उपाय अपनाएं।

कृषि विभाग ने पत्ती मोड़क कीट के नियंत्रण के लिए किसानों को क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5 प्रतिशत एससी का 6 से 10 मिलीलीटर प्रति स्प्रेयर अथवा एमामेक्टिन बेंजोएट 5 प्रतिशत एसजी का 8 से 10 ग्राम प्रति स्प्रेयर की दर से छिड़काव करने की सलाह दी है।

कृषि विभाग के अनुसार खेत में आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का उपयोग करने तथा लंबे समय तक अधिक पानी भरा रहने से कीटों के प्रकोप की स्थिति बन सकती है। किसान फसल की आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें और खेत में जलभराव की स्थिति न बनने दें। नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करने से कीटों की शुरुआती पहचान और समय पर नियंत्रण संभव होगा।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि धान की फसल में कीट प्रकोप के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करें। खेतों में नियमित निगरानी रखें और पत्तियों के पीला पड़ने, तने में छेद होने, बालियां सफेद पड़ने अथवा पत्तियों पर सफेद-पारदर्शी धारियां दिखाई देने पर तत्काल उचित नियंत्रण उपाय अपनाएं। समय पर की गई कार्रवाई से फसल को होने वाले नुकसान को कम करने के साथ बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

सो, जब विवाद चरम पर था, तब चुप्पी थी

संघ परिवार स्वयं को सांस्कृतिक और नैतिक नेतृत्व का ठेकेदार बताता है। यदि ऐसा है तो उसके प्रमुख के नाते मोहन भागवत का दायित्व बनता था कि वे इस भाषा पर तत्काल आपत्ति दर्ज कराते।

हरिशंकर व्यास

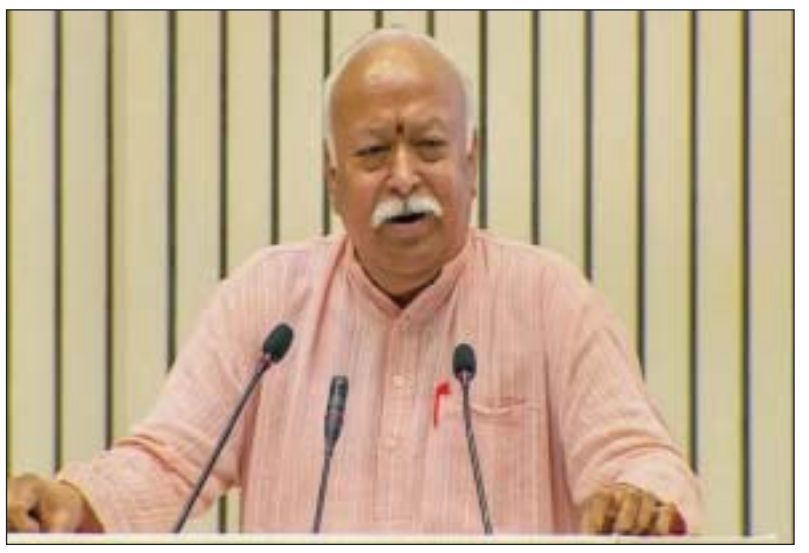

चिड़ियां खेत चुग गईं और कल, शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 'चिड़ियों को भी चुगने का अधिकार है' इतना ही नहीं वे आंख मूंदकर 'जेन-ज़ी पर भरोसा करने की बात कर रहे थे। तब प्रश्न है कि सात अगस्त 2026 को मोहन भागवत कहां थे, जब संसद मार्ग पर बच्चे-बच्चियों पर लाठियां बरस रही थीं, पैलेट गन के छर्रे दागे जा रहे थे?

या फिर 15 मई 2026 को वे किस मनःस्थिति में थे, जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली हाई कोर्ट के वकीलों को फटकारते हुए देश के ही कुछ नागरिकों को 'परजीवी और 'कॉकरोच जैसी श्रेणियों में रख दिया? ध्यान रहे, उस दिन मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता नामांकन प्रक्रिया में कथित देरी और उससे जुड़े विवाद पर सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं की पीड़ा यह थी कि वरिष्ठ पदनाम देने की प्रक्रिया में योग्यता की बजाय पक्षपात और पसंद-नापसंद हावी है। लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें यह सुनना पड़ा, 'समाज में कुछ परजीवी हैं, जो व्यवस्था पर हमला करते हैं। उन्हें रोज़गार नहीं मिलता और पेशेवर ज़िंदगी में कोई जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं'।

संघ परिवार स्वयं को सांस्कृतिक और नैतिक नेतृत्व का ठेकेदार बताता है। यदि ऐसा है तो उसके प्रमुख के नाते मोहन भागवत का दायित्व बनता था कि वे इस भाषा पर तत्काल आपत्ति दर्ज कराते। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कहते कि या तो इस शब्दावली पर सार्वजनिक खेद व्यक्त कराया जाए, या स्वयं प्रधानमंत्री स्पष्ट करें कि इस देश में कोई भी नागरिक 'कॉकरोच' नहीं है। साथ ही, सरकार औपचारिक रूप से अदालत के आगे आग्रह रखे कि इस प्रकार की शब्दावली को वापस लिया जाए।

सो, जब विवाद चरम पर था, तब चुप्पी थी। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबाले, कृष्ण गोपाल, अरुण कुमार और पूरे 'भाईसाहब नेटवर्क में रत्ती भर भी जूं नहीं रेंगी। जंतर-मंतर पर हजारों छात्र-युवा बैठे रहे। आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस उठाकर अस्पताल ले गई। विपक्ष सक्रिय हुआ। तब भी मोहन भागवत के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-सरकार्यवाह अतुल लिमये ने उलटे 'जेन-ज़ी और छात्रों के 'कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन को 'संविधान-विरोधी' और 'राष्ट्र-विरोधी' बता दिया। और अब मोहन भागवत ने कहा हैं कि 'हमें उनकी बात सुननी चाहिए। उनसे बातचीत में कमी थी, इसलिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन हुआ'।

आज जमीनी भारत का सीधा-सादा सच है कि देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। आने वाले दो दशकों तक राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था का केंद्र यही पीढ़ी रहेगी। इस पीढ़ी का पहला सरोकार शिक्षा, परीक्षा, रोजगार और कमाई है।

लेकिन पिछले बारह वर्षों में यदि किसी क्षेत्र की सर्वाधिक बरबादी हुई है तो वह शिक्षा है। कहावत है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। राजनीति का वही स्वभाव शिक्षा व्यवस्था में दिमाग, बुद्धि, काबलियत, कौशल को खा बैठा है। मोदी राज के स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल 'निशंक और धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में शिक्षा कैसी हुई? कैसे चली? 'भाईसाहब लोगों की नेटवर्किंग, भय-भूख-भक्ति की प्रवृति ने विश्वविद्यालयों को खा डाला है। खोखला बना दिया है। तुलना करें। कांग्रेस काल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, केएल श्रीमाली, हुमायूं कबीर, पीवी नरसिंह राव और डॉ. करण सिंह जैसे लोग शिक्षा मंत्री थे। वाजपेयी सरकार में डॉ. मुरली मनोहर जोशी थे। इनकी पहचान सबसे पहले एक शिक्षाविद् की थी। डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने भी अपने समय में कुलपति और उपकुलपति नियुक्त किए थे। लेकिन क्या वे इन बारह वर्षों के मोदी राज में विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के नए खोखे से खुश होंगे? योग्यता से अधिक संघ नेटवर्क और मोदी-शाह के संकेत शिक्षा के मालिकानों की ऐसी दुकान बनी है, जिसका कोई धर्म-ईमान नहीं है। शिक्षा व्यवस्था की गिरावट की नई कहानी का यही मुख्य कारण है।

तभी आश्चर्य नहीं हुआ कि जंतर-मंतर पर एकत्र छात्रों की चिंता में डॉ. मुरली मनोहर जोशी का बयान देखा। पर तब भी मोहन भागवत की नींद नहीं खुली। उनमें साहस नहीं था। शायद मान रहे होंगे अमित शाह आंदोलन को ऐसा मारेगा, ऐसा मारेगा कि नौजवान की तरूणाई भी किसानों की तरह दम तोड़ देगी। इसलिए बेकार पंगा न लो। चुप रहो। तो लडके-लड़कियां मोदी के रैप में थिरकेंगे या मोहन भागवत कीर्तन करेंगे। या मजा लेते हुए पूछेगें, 'हाय दोस्त पप्पू, क्या तुम बैकस्टेज हो?'

व्यंग्य

अब किताबे गलतियों से भरी

अब किताबे गलतियों से भरी होती है। जिसको जो मन में आया उसने किताब में लिख दिया। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का अध्याय आठवीं कक्षा की किताब में शामिल कर दिया गया, जिस पर बाद में बहुत हंगामा हुआ और किताब वापस लेनी पड़ी। ऐसा कई किताबों के मामले में हुआ है। ओडिशा की इस साल समाजशास्त्र की एक किताब में तो इतनी गलतियां हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका मजाक बना है।

उसके बाद नीतिगत स्तर पर ऐसे काम हुए, जिनका प्रत्यक्ष उद्देश्य शिक्षा में सुधार से ज्यादा विवाद पैदा करना और प्रचार पाना था। चाहे नई शिक्षा नीति हो, चाहे त्रिभाषा फॉर्मूला हो, चाहे पीएम श्री की योजना हो, कौशल विकास के लिए शुरू की गई स्किल इंडिया योजना हो या 'एक देश, एक परीक्षाO की जिद हो। इन सबका साझा असर यह हुआ कि देश के नौजवान पूरी तरह से असहाय और किंकर्तव्यविमूढ़ हुए। अंत में उसे कोई तरीका नहीं सुझा तो वह आंदोलन पर उतरा। उसके सरोकारों को समझने और उसे ठीक करने की बजाय सरकार के लोग अब उनके बातचीत के तरीके, सोशल मीडिया रील्स और मीम्स की नकल करके अपना मजाक बनवा रहे हैं। असल में अनपढ़ और कुपढ़ लोगों के हाथ में शिक्षा और परीक्षा की व्यवस्था सौंप दी गई है, जिससे नौजवान पीढ़ी के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है और जब युवा नाराज हुए हैं तो उनकी भोंड़ी नकल करके उनको पटाने की कोशिश हो रही है। इस कोशिश में लगे सब बहुत दयनीय दिख रहे है।

शिक्षा में विकास की पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया। अच्छे संस्थानों को सुनियोजित तरीके से खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए वहां अनुशासन से बंधे अपढ़ और कुपढ़ लोगों को बहाल किया गया। इसके साथ ही उन संस्थानों के क्लोन बनाने का काम भी बड़े पैमाने पर हुआ। आज बड़े गर्व से बताया जाता है कि कांग्रेस के शासन में छह आईआईटी थे, अब दो दर्जन हो गए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अब भी पहले वाले छह आईआईटी में दाखिले के लिए ही मारामारी है। ऐसे ही दर्जनों आईआईएम खुल गए, दर्जनों एम्स बन गए या बनाने की घोषणा हो गई। नए और गुणवत्तापूर्ण संस्थान बनाने की बजाय पुराने संस्थानों के क्लोन बनाने का विचार अपने आप में गड़बड़ है। सोचें, ब्रिटेन में कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि दूसरा ऑक्सफोर्ड बनाते हैं या दूसरा कैम्ब्रिज बनाते हैं। उन्होंने उस गुणवत्ता के कई संस्थान बनाए। अमेरिका में आईवी लीग के नौ कॉलेज हैं। किसी ने दूसरा हार्वर्ड या दूसरा स्टैनफोर्ड बनाने का प्रयास नहीं किया। भारत में दो दर्जन आईआईटी हो गए लेकिन अमेरिका में एक ही एमआईटी है और वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं। भारत में इतने आईआईटी, आईआईएम, एम्स और पता नहीं क्या क्या बन गए लेकिन दुनिया के सौ सबसे श्रेष्ठ संस्थानों में एक को भी जगह नहीं मिली। दोराब जी टाटा का बनवाया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी आईआईएससी एक ही हैं और वह देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है।

ब्लॉग

विकसित भारत की राह में जर्जर शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल

ललित गर्ग

भारत आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। एक शिक्षक, टूटती दीवारें और घटते सरकारी स्कूल- क्या शिक्षा के बिना 2047 का सपना पूरा होगा? दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की प्रगति, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां, आधारभूत ढांचे का विस्तार और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव निश्चित रूप से गौरव का विषय हैं। लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के पीछे यदि हम सरकारी स्कूलों की ओर देखें तो एक दूसरा भारत दिखाई देता है-ऐसा भारत जहां हजारों बच्चे आज भी पर्याप्त शिक्षकों, सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस शिक्षा-व्यवस्था पर विकसित भारत की नींव रखी जानी है, उसकी बुनियाद ही कमजोर होगी तो 2047 का भारत कितना मजबूत होगा? सरकारी आंकड़े इस चिंता को और गंभीर बनाते हैं। यूडीआईएसई प्लस 2024-25 के अनुसार देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत है और इन स्कूलों में करीब 33.77 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। यानी एक शिक्षक को कई कक्षाओं, अनेक विषयों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच बच्चों की शिक्षा संभालनी पड़ रही है। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों के भविष्य की कहानी है, जिनके लिए सरकारी स्कूल शिक्षा का सबसे सुलभ और कई बार एकमात्र माध्यम हैं।

विडंबना यह है कि उसी देश में हम विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल संस्थानों और अत्याधुनिक शिक्षण परिसरों की चर्चा करते हैं, लेकिन गांव के उस बच्चे की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो टूटी छत के नीचे बैठकर भविष्य के सपने देख रहा है। कहीं शिक्षक एक है और कक्षाएं पांच। कहीं विद्यालय भवन जर्जर है, कहीं पानी नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं बिजली और पंखे नहीं। हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में विद्यार्थियों को अधिक शिक्षक, बेहतर भोजन, पेयजल, पंखे और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। फतेहपुर में तो लगभग एक हजार विद्यार्थियों ने जर्जर कक्षाओं, रिसती छतों और सुरक्षित पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन किया। यह स्थिति केवल किसी एक राज्य अथवा किसी एक सरकार की विफलता नहीं है। यह वर्षों से चली आ रही उस प्रशासनिक सोच का परिणाम है जिसमें शिक्षा को प्राथमिकता तो भाषणों में दी गई, लेकिन उसकी गुणवत्ता और जवाबदेही को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में स्थान नहीं मिला। शिक्षा विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी व्यवस्था है, बजट है, योजनाएं हैं, समितियां हैं, निरीक्षण तंत्र है-फिर भी एक शिक्षक वाले एक लाख से अधिक स्कूल कैसे बने रहे? यह सवाल केवल सरकार से नहीं, पूरे प्रशासनिक तंत्र से पूछा जाना चाहिए।

निश्चित रूप से तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। यूडीआईएसई प्लस के अनुसार 2024-25 में देश में कुल 14.71 लाख स्कूल, करीब 24.69 करोड़ विद्यार्थी और एक करोड़ से अधिक शिक्षक हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या 10.13 लाख है, जबकि निजी मान्यता प्राप्त स्कूल करीब 3.40 लाख हैं। सरकार के आंकड़े यह भी बताते हैं कि एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 2023-24 के 1,10,971 से घटकर 2024-25 में 1,04,125 हुई है और कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूलों का अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 64.7 प्रतिशत हुआ है। इन सुधारों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इन्हें अंतिम उपलब्धि मान लेना आत्मसंतोष होगा। क्योंकि शिक्षा की असली कसौटी भवन, कंप्यूटर या आंकड़े नहीं, बच्चे की सीखने की क्षमता और उसके भविष्य का निर्माण है।

नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट एक और महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखती है। 2014-15 में देश में 11.07 लाख सरकारी स्कूल थे, जो 2024-25 में घटकर 10.13 लाख रह गए। इसके विपरीत निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर 3.39 लाख हो गई। यह परिवर्तन केवल स्कूलों की संख्या का उतार-चढ़ाव नहीं है, यह अभिभावकों की बदलती पसंद और सरकारी शिक्षा में घटते विश्वास का संकेत भी है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब सरकार के पास भवन है, जमीन है, प्रशिक्षित शिक्षक हैं, वेतन देने की क्षमता है और विशाल प्रशासनिक तंत्र है, तब सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से पीछे क्यों हैं? निजी स्कूलों की आलोचना करना आसान है, लेकिन यह भी देखना होगा कि अभिभावक अपनी सीमित आय में फीस देकर भी निजी स्कूल क्यों चुन रहे हैं। इसका उत्तर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, अनुशासन, नियमितता, अंग्रेजी एवं तकनीकी शिक्षा, अभिभावक संवाद और सीखने के वातावरण में छिपा है। एसीईआर के आंकड़े भी इस अंतर को रेखांकित करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कक्षा 3 के बच्चों में कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ पाने वालों का अनुपात सरकारी स्कूलों में 23.4 प्रतिशत था, जबकि निजी स्कूलों में 35.5 प्रतिशत। कक्षा 5 में भी सरकारी स्कूलों का आंकड़ा 44.8 प्रतिशत और निजी स्कूलों का 59.3 प्रतिशत रहा। यानी समस्या केवल स्कूल भवन की नहीं, सीखने के परिणामों की भी है।

इसी के समानांतर उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तस्वीर भी चिंता पैदा करती है। पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितता, भर्ती में देरी और युवाओं के आंदोलनों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। 2026 में परीक्षा संबंधी विवादों ने विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों में असंतोष को व्यापक बनाया। इसका अर्थ यह है कि समस्या शिक्षा-व्यवस्था के निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक फैली हुई है। प्राथमिक स्कूल में कमजोर नींव, माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता का संकट और उच्च शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता का सवाल-इन सबको अलग-अलग देखकर समाधान नहीं निकलेगा। सरकारी स्कूल वास्तव में भारत की सामाजिक समानता का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन स्कूलों में ग्रामीण परिवारों, श्रमिकों, गरीबों, वंचित वर्गों और निम्न आय वाले परिवारों के बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। यदि इन विद्यालयों की गुणवत्ता गिरती है तो सबसे अधिक नुकसान उसी वर्ग को होता है जिसके पास महंगे निजी स्कूलों का विकल्प नहीं है। इसलिए सरकारी स्कूलों की बदहाली केवल शिक्षा का संकट नहीं, सामाजिक न्याय का संकट भी है।

यहां एक कठोर लेकिन सार्थक सुझाव पर विचार होना चाहिए-क्या जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चों के लिए कुछ निश्चित परिस्थितियों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा को प्रोत्साहित अथवा अनिवार्य करने जैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है? जब नीति बनाने वाले परिवार स्वयं उसी व्यवस्था का अनुभव करेंगे, तब शायद स्कूल की टूटी खिड़की, बंद शौचालय, शिक्षक की कमी और खराब मिड-डे-मील केवल फाइल की टिप्पणी नहीं रहेंगे, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव बन जाएंगे। शिक्षा को केवल मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म या मुफ्त पुस्तकों की योजनाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। ये आवश्यक हैं, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना नहीं, उसे ज्ञान, विवेक, कौशल, संस्कार और आत्मविश्वास से संपन्न नागरिक बनाना है। जिस बच्चे को आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, उससे कल विकसित भारत के निर्माण में प्रभावी योगदान की अपेक्षा कैसे की जा सकती है?

सरकार को अब घोषणाओं से आगे बढ़कर 'राष्ट्रीय सरकारी स्कूल कायाकल्प मिशन' जैसी व्यापक पहल पर विचार करना चाहिए। प्रत्येक स्कूल के लिए शिक्षक उपलब्धता, भवन की सुरक्षा, पेयजल, बिजली, डिजिटल सुविधा, शौचालय, पुस्तकालय, खेल मैदान और सीखने के परिणामों के स्पष्ट मानक तय हों। हर स्कूल का सार्वजनिक डैशबोर्ड हो और हर वर्ष यह बताया जाए कि कितने बच्चे पढ़ना, लिखना और गणित करना सीख पाए। शिक्षक नियुक्ति में पारदर्शिता हो और राजनीतिक हस्तक्षेप पर कठोर अंकुश लगे। स्कूल प्रबंधन समितियों को वास्तविक अधिकार दिए जाएं तथा जिला स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। सबसे जरूरी है कि शिक्षा को राजनीति से ऊपर उठाया जाए। सरकार और विपक्ष दोनों को यह समझना होगा कि सरकारी स्कूल किसी पार्टी के नहीं, भारत के भविष्य के स्कूल हैं। यदि किसी राजनीतिक दल को स्कूलों की बदहाली दिखाई देती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन मुद्दा राजनीतिक श्रेय का नहीं, बच्चों के भविष्य का होना चाहिए।

कानपुर में ट्रेनी विमान क्रैश: अचानक नत्थूपुरवा के खेतों में गिरा, गूंजी धमाके की आवाज; दोनों पायलट की मौत

कानपुर के गंगा बैराज के पास करीब 11:50 बजे हुआ हादसा

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। कानपुर के कटरी क्षेत्र में गुरुवार दोपहर नत्थूपुरवा गांव के पास एक ट्रेनिंग विमान (ट्रेनी एयरक्राफ्ट) अचानक अनियंत्रित होकर खेतों में जा गिरा। इस भीषण दुर्घटना में विमान में सवार दोनों ट्रेनी पायलट की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्विन इंजन का यह ट्रेनिंग विमान अचानक तेज आवाज के साथ खेतों में आ गिरा। दुर्घटना के तुरंत बाद इलाके में भारी अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। अचानक हुए इस हादसे से पूरे गांव में दहशत का माहौल है।

नत्था खेड़ा गंगा बैराज कानपुर के पास ट्रेनिंग विमान/एयरक्राफ्ट गिरने की सूचना पर सीएफओ महोदय की उपस्थिति में अग्निशमन तथा आपात सेवा कानपुर नगर की रेस्क्यू टीमें मौके पर राहत एवं बचाव कार्य कर रही है।

नत्था खेड़ा गंगा बैराज कानपुर के पास ट्रेनिंग विमान/एयरक्राफ्ट गिरने की सूचना पर सीएफओ महोदय की उपस्थिति में अग्निशमन तथा आपात सेवा कानपुर नगर की रेस्क्यू टीमें मौके पर राहत एवं बचाव कार्य कर रही है।

घायल पायलट हैलट अस्पताल में भर्ती

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए पुलिस ने विमान के मलबे से दोनों पायलटों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल एक ट्रेनी पायलट को तुरंत इलाज के लिए हैलट अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी भी मौत हो गई है।

गुजरात के इंस्ट्रक्टर और कर्नाटक के ट्रेनी की मौत

पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि गार्ग एविएशन का टेक्नाम एयरक्राफ्ट सुबह करीब 11:30 बजे उड़ा और लगभग 20 मिनट बाद कटरी इलाके के नथापुरवा गांव के पास क्रैश हो गया। क्रैश की वजह का तुरंत पता नहीं चल सका है। बताया कि इस हादसे में गुजरात के इंस्ट्रक्टर सचिन भाटिया और कर्नाटक के ट्रेनी पायलट अभिषेक पुजारी की मौत हो गई।

डीजीसीए करेगा जांच

उन्होंने बताया कि भाटिया को करीब 3,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, इलाके की घेराबंदी की और जांच के लिए सबूत के तौर पर एयरक्राफ्ट के मलबे को सुरक्षित किया। पुलिस ने बताया कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट की एयरवर्दीनेस, मेंटेनेंस रिकॉर्ड और दूसरी तकनीकी बातों की जांच करेगा।

कंपनी का दावा- इस एयरक्राफ्ट में मेंटेनेंस से जुड़ी कोई कमी नहीं थी

शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि यह दो इंजन वाला एयरक्राफ्ट था। क्रैश वाली जगह के वीडियो में एयरक्राफ्ट पूरी तरह से मलबे में तब्दील दिखाई दिया और आसपास मलबा बिखरा हुआ था। मलबे के बाहर एक सीट भी देखी गई, हालांकि अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि पायलटों ने प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश की थी या नहीं। कंपनी का दावा है कि 2023 से गार्ग एविएशन के पास मौजूद इस एयरक्राफ्ट में मेंटेनेंस से जुड़ी कोई कमी नहीं थी।

निकाली जाएगी भोजवाल जागृति यात्रा

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से श्री अन्नकला बोर्ड के गठन के निर्णय का भोजवाल समाज ने स्वागत करते हुए आभार जताया। समाज को अधिकारों के प्रति जागरूक करने और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से आगामी 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश भोजवाल जागृति यात्रा निकाली जाएगी। यह घोषणा भोजवाल फाउंडेशन की ओर से आयोजित प्रेसवार्ता में अध्यक्ष अरुण भोजवाल 'आजाद' ने की।फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष इंजीनियर उमाशंकर भोजवाल ने कहा कि भुर्जी समाज लंबे समय से अपनी पाक कला और अन्नकला की परंपरा के माध्यम से लोगों को सेवाएं देता आ रहा है। श्री अन्नकला बोर्ड के गठन से समाज के युवाओं को होटल, रेस्टोरेंट, फूड प्रोसेसिंग और कैटरिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा पारंपरिक हुनर को सरकारी पहचान भी मिल सकेगी।उपाध्यक्ष रामजी भोजवाल ने कहा कि बोर्ड में समाज के अनुभवी और जमीनी कार्यकर्ताओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।अध्यक्ष अरुण भोजवाल 'आजाद' ने कहा कि जागृति यात्रा के दौरान भुर्जी-भोजवाल समाज को पिछड़े वर्ग में सर्वाधिक पिछड़ा घोषित करने की मांग भी उठाई जाएगी। साथ ही विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विभिन्न आयोगों में समाज को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की जाएगी।महासचिव डॉ. मनोहर गुप्ता 'कानू' ने कहा कि स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद भी उत्तर प्रदेश में समाज का कोई सांसद या विधायक नहीं है।

पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जान लें चीनी का फुटकर भाव, चाय की अड़ियों पर भी जानें प्रभाव

आर्यावर्त संवाददाता

वाराणसी। देश भर में चीनी का भाव स्वाद कसैला करने पर उतारू है तो पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय सीट में भी चीनी का भाव आसमान पर है। यहां चाय की अड़ियों पर कुछ जगहों पर कीमतों में एक रुपये का इजाफा हो गया है तो कुछ दुकानों पर कप का साइज छोटा हो गया है। यानी चुस्कियों पर भी राष्ट्रीय पेय का स्वाद बगिड़ा है।

चीनी की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली। फुटकर बाजार में चीनी के भाव में दो रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है। एक सप्ताह पहले 65 रुपये किलो बिक रही चीनी अब 63 रुपये किलो हो गई है। थोक मंडी में कीमत घटने का असर फुटकर बाजार में भी देखने को मिला।

खोजवां बाजार के किराना दुकानदार सचिन ने बताया कि एक सप्ताह पहले चीनी का भाव बढ़कर 65 रुपये प्रति किलो पहुंच गया था। मंगलवार दोपहर बाद थोक मंडी में

कीमत कम होने के बाद फुटकर भाव में भी गिरावट आई। थोक मंडी से मंगलवार को 6100 से 6200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चीनी की आवक हुई।

एक सप्ताह पहले यह 6400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। विश्वेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रतीक कुमार गुप्ता ने बताया कि चीनी की थोक कीमत में 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। महाराष्ट्र में चीनी के भाव में करीब एक हजार रुपये प्रति क्विंटल की कमी आने से थोक बाजार में कीमतों में तेजी नहीं आई है।

एडीएम आपूर्ति अमित कुमार ने दो दिन पूर्व ही थोक चीनी विक्रेताओं के साथ बैठक कर कालाबाजारी व जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए प्रतिदिन स्टाक को पोर्टल पर अपडेट करने का आदेश दिया था। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को रिपोर्ट देनी थी। व्यापारियों ने भी सहमति जताई थी।

खेलों से जुड़ें युवा, नशे से रहें दूर: राज्यमंत्री

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना एवं मेरा युवा भारत, के संयुक्त तत्वावधान में 'खेलो इंडिया संवादकृखेल की बात, पीएम के साथ' कार्यक्रम आर्यभट्ट सभागार, रज्जू भैया संस्थान में संपन्न हुआ। हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम को टीवी पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं से खेलों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने और भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने का आह्वान किया। विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि गिरीश चंद्र यादव ने युवाओं से खेलों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने, अपनी प्रतिभा को निखारने तथा नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ, अनुशासित एवं ऊर्जावान युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं। एथलेटिक्स खिलाड़ी सुश्री पूजा यादव को मुख्य अतिथि ने अंगवस्त्रं देकर सम्मानित किया।

नेपाल में जल प्रलय : कुशीनगर में एडीआरएफ की क्षेत्रीय बचाव दल अलर्ट, गंडक नदी की निगरानी

आर्यावर्त संवाददाता

वाराणसी। नेपाल में अचानक तब्बित की ओर से आए जल प्रलय के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में संभावित संकटों को रोकने के लिए एनडीआरएफ की 11वीं बटालियन की 35 सदस्यीय टीम को कुशीनगर जनपद के खड्डा में अलर्ट किया गया है।

यह टीम गोरखपुर में रीजन रेस्क्यू सेंटर से भेजी गई है, जो वाराणसी मुख्यालय का हिस्सा है। कमांडेंट अनूप सिंह बष्टि के अनुसार व्यवस्थाएं पूरी हैं, जैसी स्थिति होगी टीम उसी अनुरूप सक्रियता के साथ काम करेगी। आशंका है कि नेपाल के जल प्रलय का प्रभाव बिहार के गंडक नदी में जल वृद्धि के रूप में सामने आ सकता है, जिससे जनहानि की आशंका बढ़ गई है।

नेपाल की त्रिशूली और भोटेकोशी नदियों में आई बाढ़ का

पानी आगे चलकर नारायणी नदी में पहुंचा है, जिसे भारत में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे अधिक असर बिहार के गंडक नदी से लगे जिलों जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में पड़ने की आशंका है।

एनडीआरएफ के सूत्रों के अनुसार, रीजन रेस्क्यू सेंटर की 35 सदस्यीय टीम को विभिन्न जीवन रक्षक उपकरणों से लैस किया गया है। इनमें लाइफ जैकेट, लाइफ बाय, इन्फ्लेटेबल रेस्क्यू बोट, रेस्क्यू बोट, ओबीएम, पर्सनल डाइविंग किट, आक्सीजन/ब्रीदिंग सिलिंडर, अंडरवाटर कम्युनिकेशन सेट, अंडरवाटर टार्च, नायलान रेस्क्यू रोप, प्न्यूमेटिक रोप लांचन, रिमोट कंट्रोल्ड लाइफ ब्वाय, फ्लोटिंग पंप, रेस्क्यू बैक बोर्ड, बास्केट स्ट्रेचर और फिशिंग नेट शामिल हैं।

इन संसाधनों के माध्यम से टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। गंडक नदी के जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है, जिससे बिहार के जिलों में संभावित प्रभाव का आकलन किया जा सके।

वाराणसी मुख्यालय की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से निर्देश मलिने के बाद टीमें नेपाल की ओर भी रवाना हो सकती हैं। इस लहिाज से टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

निजी डेटा जुटाने के विरोध में एसयूसीआई का विरोध

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। जिला प्रशासन व खुफिया तंत्र के द्वारा एसयूसीआई (सी) के नेताओं व पदाधिकारियों पर प्रशासनिक दबाव डालने व उनके निजी डेटा जुटाने के विरोध में एसयूसीआई (सी) का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड रविशंकर मौर्य ने कहा कि, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में राजनीतिक विरोध और जन-आंदोलनों को कुचलने के लिए प्रशासन व खुफिया तंत्र के जरिए पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी में गैर-कानूनी दखलंदाजी की जा रही है। प्रशासन द्वारा बाकायदा दबाव बनाकर नेताओं से उनके परिवार, रिश्तेदारों, निजी फोटो, बैंक खातों के विवरण, आय के स्रोत, सोशल मीडिया प्रोफाइल, पहचान पत्र, संपत्ति विवाद, अन्य मुकदमें और निजी संपर्कों तक का ब्योरा मांगा जा रहा है। क्या यह निजता के मौलिक अधिकार का खुला उल्लंघन नहीं है ? पूछे जाने पर प्रशासन द्वारा कोई उचित व नैतिक कारण भी नहीं बताया जा रहा है। पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को प्रशासन व खुफिया तंत्र द्वारा फोन करके, घर पहुंच करके जैसे भी हो उन पर दबाव बनाते हुए उनकी निजी जानकारी जुटाने और परिवार जनों में पुलिसिया भय पैदा करने का काम किया जा रहा है। यह प्रशासनिक हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि पार्टी व राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर प्रताड़ित करने और उनका निजी डेटा जुटाने की यह तानाशाही प्रक्रिया तुरंत बंद नहीं हुई, तो पार्टी व्यापक जन-आन्दोलन संगठित करके सड़कों पर उतरने को विवश होगी।

इश्क में तोड़ी मजहब की दीवार : बिहार की सोनम खातून ने किया धर्म परिवर्तन, बरेली में प्रेमी से रचाई शादी

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। बिहार के बेगूसराय जिले की सोनम खातून ने बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम में हिंदू धर्म अपना लिया। उन्होंने अपना नाम सोनम देवी रख लिया और बरेली के भोजीपुरा निवासी प्रेमी संजीव से शादी कर ली। दोनों की प्रेम कहानी इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुई थी।

आश्रम में आचार्य केके शंखधार ने सोनम खातून की पहले वैदिक रीति से धर्म परिवर्तन कराया। सोनम ने बताया कि वह बेगूसराय के पचवीर की निवासी हैं। पांच वर्षों से हिंदू धर्म में उनकी आस्था है। राधा-कृष्ण को अपना आराध्य मानती रही हैं। उनके पिता का नाम अकबर और मां का नाम शहनाज खातून है। सोनम छह बहनें और एक भाई हैं, जिसमें वह तीसरे नंबर की हैं। सोनम ने बताया कि उनके पिता वेल्डिंग का काम करते हैं। गुजरात में काम करने के दौरान उनकी पहचान बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव बुझिया शुमाली निवासी संजीव से हुई थी। दोनों अलग-अलग कारखानों में काम करते थे पर उनके कमरे आमने-सामने थे। अब उन्होंने शादी करके साथ रहने का फैसला कर लिया है। सोमन ने बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। वह संजीव से शादी कर खुश हैं। संजीव ने भी जिंदगीभर साथ निभाने का वादा किया।

इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यार

सोनम ने बताया कि संजीव से उनकी बातचीत इंस्टाग्राम के जरिये शुरू हुई थी। संजीव ने पहले उससे प्रेम का इजहार किया था। जवाब में सोनम ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपना रही हैं।

विवि के इंक्यूबेशन सेंटर को मान्यता प्रमाण पत्र

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति को गति देने के उद्देश्य से लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, के इंक्यूबेशन सेंटर को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मान्यता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह एवं इंक्यूबेशन सेंटर के कार्यकारी निदेशक प्रो. अविनाश पाथर्डीकर को यह प्रमाण पत्र प्रदान किया। कुलपति ने बताया कि इंक्यूबेशन सेंटर को मिली इस मान्यता से विश्वविद्यालय से जुड़ने वाले स्टार्टअप एवं इनक्यूबेटीज को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। विशेष रूप से सीड फंडिंग, प्रोत्साहन राशि तथा स्टार्टअप विकास से संबंधित अन्य

सरकारी सुविधाओं तक उनकी पहुंच अधिक सुगम हो सकेगी। इससे विश्वविद्यालय में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त होगा। सेंटर के कार्यकारी निदेशक ने बताया कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर को मिली मान्यता को विश्वविद्यालय में नवाचार एवं उद्यमिता को संस्थागत रूप से मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे पूर्वांचल क्षेत्र के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और नवोदित उद्यमियों को अपने विचारों को स्टार्टअप में परिवर्तित करने तथा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे...' जिस गाने ने अंकित बालियान को दिलाई शोहरत, क्या वही बना हत्या की वजह? सामने आया गोगी गैंग का कनेक्शन

आर्यावर्त संवाददाता

शामली। हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या ने हिलाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में अंकित बालियान की बीते बुधवार गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। पोस्ट में भोलू शाहपुरिया नाम के शख्स ने अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। हालांकि, इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं हुई है।

वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अंकित बालियान को इसलिए निशाना बनाया गया, क्योंकि उन्होंने गोगी गैंग के प्रमुख से जुड़ी एक घटना पर गाना बनाया था। पोस्ट में लिखा गया, अंकित हमारे दुश्मनों से मिला था। हमारे भाई पर हुई घटना पर गाना बनाया था। ये अभी शुरुआत

है, सबका नंबर आएगा।

अंकित बालियान जेल, गैंगवार और अपराध की दुनिया पर आधारित गीतों के लिए खास तौर पर चर्चित थे। उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता जज के भी आवेंगे पसीने, देखिए भरी कोर्ट में गोली मारेंगे... गाने से मिली। इस गाने को दर्शकों ने खूब पसंद किया और यूट्यूब पर इसे 5।4 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। बताया जाता है कि यह गीत कुख्यात बदमाश की कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या की घटना की थीम पर आधारित था। यह गाना 15 फरवरी 2023 को रिलीज हुआ था।

इस पोस्ट के सामने आने के बाद हत्या को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, पुलिस जांच पूरी होने से पहले सोशल मीडिया पर सामने आए इस दावे को हत्या की वजह या गैंग की संलिप्तता के तौर पर पुख्ता नहीं माना जा सकता। पुलिस फिलहाल सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है।

जिम से बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग

जानकारी के मुताबिक, अंकित बालियान बुधवार शाम रोजाना की तरह जिम गए थे। शाम करीब 6:45 बजे जब वह जिम से बाहर निकले, तभी पहले से घात लगाए हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं। बताया जा रहा है कि हमलावर दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने बेहद कम समय में कई राउंड फायर किए। कुछ रिपोर्टों में 20 से ज्यादा गोलियां चलने की बात कही जा रही है। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। गोली लगने से अंकित गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमलावरों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक, वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर कौन थे और वारदात को अंजाम देने के बाद वे किस दिशा में फरार हुए। जांच में यह पहलू भी शामिल है कि क्या हमलावरों ने अंकित की पहले से रेकी की थी।

क्या दिनचर्या की जानकारी थी हमलावरों को?

जिस तरह जिम से बाहर निकलते ही अंकित बालियान को निशाना बनाया गया, उससे पुलिस इस संभावना की भी जांच कर रही है कि हमलावरों को उनकी दिनचर्या और जिम से निकलने के समय की जानकारी थी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हमलावरों ने उन्हें पहले से ट्रैक किया था या फिर मौके पर पहुंचकर हमला किया। हत्या की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में गोगी गैंग से जुड़े होने का दावा किया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

पंचायत चुनाव लड़ने की भी चर्चा

अंकित बालियान की हत्या के बाद यह चर्चा भी सामने आई कि वह आगामी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि, अधिकारियों या उनके सहयोगियों की ओर से इस संबंध में तत्काल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि चुनाव लड़ने की कथित तैयारी का उनकी हत्या से कोई संबंध था या नहीं।

पहले भी विवादों में रहे थे अंकित

अंकित बालियान इससे पहले भी विवादों को लेकर चर्चा में रह चुके थे। जुलाई 2023 में शामली में उनके काफिले के रोड शो के मामले में पुलिस ने अंकित समेत करीब 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि, मौजूदा हत्या की घटना से उस मामले का कोई संबंध है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

अंकित बालियान के यूट्यूब चैनल पर 3।66 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे। वह हरियाणवी संगीत और वीडियो के जरिए अपनी पहचान बना चुके थे। उनके कई वीडियो में सहयोगियों के साथ-साथ हथियार, बंदूक और एसयूवी भी नजर आती थीं। अब पुलिस उनकी हत्या के पीछे की असली वजह और हमलावरों की पहचान का पता लगाने में जुटी है।

एच1एन1 के बढ़ते मामले! फ्लू की वैक्सीन पर आईसीएमआर ने क्या कहा?

दिल्ली में एच1एन1 के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच आईसीएमआर ने फ्लू के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन पर बयान दिया। जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

आईसीएमआर ने कहा है कि देश में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू यानी एच1एन1 के मामले किसी नए वायरस या नए स्ट्रेन के कारण नहीं हैं। मौजूदा एच1एन1 वायरस पुराना और जाना-पहचाना मौसमी वैरिएंट है, जो वर्ष 2025 से प्रचलन में है। इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर के अनुसार, मौजूदा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एच1एन1 वायरस के खिलाफ प्रभावी है। हालांकि, कोविड वैक्सीन की तरह फ्लू वैक्सीन सभी लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है। बाजार में फ्लू की दो-तीन वैक्सीन उपलब्ध हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से इन्हें लिया जा सकता है।

मौसम में बदलाव और मानसून के दौरान सांस से फैलने वाले संक्रमणों की सक्रियता बढ़ने के कारण एच1एन1 के मामलों में इजाफा देखा गया। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और बदन दर्द शामिल हैं। ज्यादातर मामलों में मरीज उचित आराम और इलाज से चार-पांच दिनों में ठीक हो जाते हैं।

ये लोग ज्यादा सावधानी बरतें

आईसीएमआर ने बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टर सुचिन बजाज (एमबीबीएस, एमडी, एफआईसीबी, एफआरएसए, एफआईएसीएम) का कहना है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में इंफ्लुएंजा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। खासकर अगर साथ में डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी की बीमारी, अस्थमा या सीओपीडी जैसी कोई बीमारी पहले से हो।

फ्लू के खिलाफ कैसी है तैयारी

आईसीएमआर के मुताबिक, देश में एच1एन1 के मामले कुछ समय पहले बढ़े थे, लेकिन अब इनमें धीरे-धीरे कमी आ रही है। दिल्ली में भी पिछले चार-पांच सप्ताह के दौरान संक्रमण के मामले ज्यादा रहे, हालांकि पिछले करीब दो सप्ताह में मामलों में गिरावट देखी गई है। इस सप्ताह के आंकड़ों का अभी इंतजार है। आईसीएमआर ने बताया कि दिल्ली के 73 अस्पतालों में फ्लू की निगरानी की जा रही है। लैब में नियमित रूप से सैंपल की जांच की जा रही है और हर सप्ताह करीब 25 सैंपल की टेस्टिंग की जा रही है।

फ्लू के दिल्ली में 650 मामले

राजधानी दिल्ली में अब तक करीब 650 फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। आईसीएमआर के मुताबिक, सामान्य फ्लू के लक्षण होने पर हर व्यक्ति को तुरंत टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

बचाव के लिए सलाह

दिन में कई बार हाथ साबुन से धोएं।

खांसी-जुकाम से पीड़ित लोगों से उचित दूरी बनाए रखें।

खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक ढकें।

बुजुर्ग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारी वाले लोग विशेष सावधानी बरतें।

लक्षण गंभीर होने पर डॉक्टर से सलाह लें।

आईसीएमआर का कहना है कि फिलहाल H1N1 को लेकर ज्यादा चिंता या घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्हें फ्लू के लक्षण महसूस हो रहे हैं वो मास्क पहनकर रखें। साथ ही लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर चलें।

मास्क लगाने, दो गज की दूरी की सलाह

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भीड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने, दो गज की शारीरिक दूरी रखने और श्वसन स्वच्छता का पालन करने की सलाह दी है। बुखार, खांसी या छींक जैसे लक्षण होने पर सार्वजनिक स्थानों से दूरी रखने और चिकित्सकीय सलाह लेने को कहा गया है।

रात में सोने से एक घंटे पहले फोन बंद करना

खराब नींद, दिनभर थकान, आंखों में दर्द या चुभन और ऐसी कई समस्याएं लोगों को लगातार बनी हुई है। दिमाग और आंखों पर इस बुरे असर की एक बड़ी वजह मोबाइल भी है। लोग घंटों स्क्रीन देखते हैं जिसमें रील्स को देखना सबसे कॉमन है। दिक्कत और तब बढ़ती है जब रात में सोने से पहले लोग लगातार देर तक फोन देखते हैं। अंधेरे में फोन की ब्लू लाइट कई तरीकों से हमें नुकसान पहुंचाती है।

वैसे अब लोग ये समझने लगे हैं कि फोन की लत कैसे हमारे लिए खतरा बनती जा रही है। इसमें सोने से एक घंटे पहले फोन को न छूने की सलाह दी जाती है। पर क्या आपने सोचा है कि आखिर सोने से एक घंटे पहले फोन यूज न करने से शरीर में क्या होता है?

एक्सपर्ट ने क्या कहा?

डॉक्टर अमित कुमार मंडल (सीनियर डायरेक्टर, पल्मोनोलॉजी, पारस हेल्थ हॉस्पिटल) सोने से कम से कम एक घंटे पहले फोन को दूर रखने या बंद करने से शरीर और दिमाग को नींद के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार होने का समय मिलता है। हमारी नींद और जागने की प्रक्रिया शरीर की सर्केडियन रिदम से नियंत्रित होती है। रात में मोबाइल फोन और अन्य स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी, विशेषकर नीली रोशनी, मेलाटोनिन हार्मोन के स्राव को प्रभावित कर सकती है। मेलाटोनिन शरीर को संकेत देता है कि अब आराम और नींद का समय है। इसलिए सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाने से नींद आने की प्रक्रिया आसान हो सकती है।

नींद के पैटर्न पर बुरा असर

इसका फायदा केवल स्क्रीन की रोशनी कम होने तक सीमित नहीं है। मोबाइल पर सोशल मीडिया, वीडियो, समाचार, काम से जुड़े संदेश या लगातार नोटिफिकेशन देखना दिमाग को सक्रिय बनाए रख सकता है। कई बार व्यक्ति कुछ मिनट के लिए फोन देखने के इरादे से शुरू करता है, लेकिन स्क्रीन पर अधिक समय बिताने के कारण सोने का समय आगे बढ़ जाता है। इससे नींद की कुल अवधि भी कम हो सकती है।

फोन नहीं किताब पढ़ें

सोने से एक घंटा पहले फोन अलग रखने की आदत दिमाग को शांत होने और शरीर को नींद के लिए तैयार होने का अवसर देती है। इस दौरान किताब पढ़ना, हल्की स्ट्रेचिंग, ध्यान या परिवार के साथ शांत बातचीत जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि केवल फोन बंद करना हर तरह की नींद की समस्या का समाधान नहीं है। पर्याप्त नींद, नियमित सोने-जागने का समय और स्वस्थ दिनचर्या भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसे नियमित आदत बनाना नींद की गुणवत्ता और अगले दिन की ऊर्जा के लिए अधिक लाभकारी हो सकता है।

खांसी से छुटकारा पाना चाहते हैं? आज ही आजमाएं ये 5 घरेलू उपाय

खांसी एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। यह समस्या कई कारणों से होती है, जैसे ठंड, धूल-मिट्टी और धूम्रपान आदि। खांसी होने पर गले में खुजली, खराश और बलगम जैसी समस्याएं होती हैं, जिससे आराम मिलना मुश्किल हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप आसानी से खांसी से छुटकारा पा सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं।

अदरक का रस पीएं

अदरक का रस खांसी के लिए एक असरदार घरेलू उपाय है। इसमें मौजूद खास गुण गले की सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

इसके लिए एक छोटे टुकड़े अदरक को कद्दूकस करके उसका रस निकालें और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर पीएं। यह मिश्रण गले की खराश को भी दूर करता है और खांसी को कम करता है।

अदरक का रस पीने से आपको ताजगी और आराम महसूस होगा।

तुलसी की चाय बनाकर पीएं

तुलसी की चाय खांसी के लिए एक अच्छा उपाय हो सकती है। तुलसी में मौजूद गुण आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं और खांसी को दूर करते हैं।

इसके लिए कुछ तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालें और उसमें थोड़ा-सा गुड़ डालें, फिर इसे छानकर पीएं।

यह चाय न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि आपके गले को भी राहत देती है और खांसी को कम करने में मदद करती है।

शहद और नींबू का मिश्रण लें

शहद और नींबू का मिश्रण खांसी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और शहद की मिठास गले को सुकून देती है।

इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर पीएं।

यह मिश्रण खांसी को कम करने के साथ-साथ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है और आपको जल्दी आराम मिलता है।

लहसुन की कली चबाएं

लहसुन की कली चबाना खांसी के लिए एक पुराना और असरदार तरीका है। लहसुन में मौजूद गुण संक्रमण को दूर करते हैं और खांसी को कम करते हैं।

इसके लिए एक लहसुन की कली को चबाकर उसका रस निकालें या उसे थोड़ा कच्चा खा लें। इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी।

लहसुन का सेवन करने से गले की सूजन भी कम होती है।

नमक वाले गर्म पानी से गरारे करें

नमक वाले गर्म पानी से गरारे करना गले की सूजन कम करने का एक अच्छा तरीका है। नमक में मौजूद गुण बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और दर्द निवारक का काम करते हैं।

इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर गरारे करें। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी।

इन उपायों को अपनाकर आप आसानी से खांसी से छुटकारा पा सकते हैं।

जेन-ज़ी को क्यों हो रही है ज्यादा बाल झड़ने की समस्या?

गलत

बालों का झड़ना एक आम समस्या है, जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, हाल के अध्ययन बताते हैं कि जनरेशन (जेन-ज़ी) यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों में बालों का झड़ना तेजी से बढ़ रहा है। यह समस्या खासकर महिलाओं में अधिक देखी जा रही है। आइए जानते हैं कि क्यों बालों का झड़ना जेन-ज़ी के लोगों में अधिक देखा जा रहा है।

तनाव और मानसिक स्वास्थ्य

जेन-ज़ी के लोग अक्सर मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तनाव, चिंता और अवसाद जैसे मुद्दे उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं।

इन समस्याओं का असर न केवल मानसिक, बल्कि शारीरिक सेहत पर भी पड़ता है। बालों का झड़ना भी इसका एक लक्षण हो सकता है।

जब व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है तो उसका शरीर भी प्रभावित होता है, जिससे बाल तेजी से झड़ने लगते हैं।

सोशल मीडिया का प्रभाव

सोशल मीडिया ने जेन-ज़ी पर गहरा असर डाला है। वे अपने जीवन की हर छोटी-बड़ी घटना को सोशल मीडिया पर साझा करते हैं और दूसरों की तुलना करते हैं।

इससे उन्हें आत्म-सम्मान की कमी और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का असर उनके बालों पर पड़ता है, जिससे बाल तेजी से झड़ने लगते हैं।

साथ ही सोशल मीडिया पर सुझाए उत्पाद चुनना भी एक कारण है।

खान-पान और पोषण की कमी

आजकल के लोग फास्ट फूड और जंक फूड का सेवन ज्यादा करते हैं, जो पोषण से भरपूर नहीं होते और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। सही पोषण न मिलने से बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं।

सही खान-पान से बालों की सेहत बेहतर हो सकती है। इसके लिए हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन युक्त आहार और पानी का सेवन बढ़ाना जरूरी है।

साथ ही विटामिन और मिनरल की कमी को दूर करने पर ध्यान दें।

हेयर स्टाइलिंग उपकरणों का अत्यधिक उपयोग

हेयर स्टाइलिंग उपकरण, जैसे स्ट्रेटनर और कर्लर आदि का अत्यधिक उपयोग भी बालों के झड़ने का कारण बन सकता है। इन उपकरणों से बालों को सीधा या घुमा कर स्टाइल किया जाता है, लेकिन इनकी गर्मी से बाल कमजोर हो जाते हैं।

इसलिए, इनका उपयोग कम से कम करें और प्राकृतिक तरीकों से हेयर स्टाइलिंग करें। इसके अलावा हेयर स्टाइलिंग के लिए प्राकृतिक उपायों का उपयोग करें, ताकि बाल स्वस्थ रहें और झड़ने की संभावना कम हो।

केमिकल युक्त हेयर उत्पाद का इस्तेमाल

बाजार में कई तरह के हेयर उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनमें रासायनिक तत्व होते हैं, जो बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। जेन-ज़ी के लोग अक्सर इन उत्पादों का इस्तेमाल करते समय इनकी गुणवत्ता या सामग्री पर ध्यान नहीं देते, जिससे उनके बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं।

इन कारणों से साफ है कि बालों का झड़ना जेन-ज़ी के लोगों में एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिससे निजात पाने के लिए उन्हें इन समस्याओं पर ध्यान देना होगा।

2023 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगी ₹25 लाख की लीव एनकैशमेंट छूट

ITAT (आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण) के हालिया फैसले के अनुसार 2023 से पहले रिटायर्ड हुए प्राइवेट व PSU कर्मचारी भी लीव एनकैशमेंट पर 25 लाख रुपए तक की बढ़ी हुई टैक्स छूट की अपील कर सकते हैं।

जो रिटायर होने वाले कर्मचारी 2023 से पहले लीव एनकैशमेंट (छुट्टी के बदले नकद भुगतान) पर टैक्स छूट के तौर पर सिर्फ 3 लाख रुपए पाते थे, उन्हें अब राहत मिल सकती है। चेन्नई में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने हाल ही में एक आदेश में कहा है कि 24 मई 2023 को लागू की गई 25 लाख रुपए की बढ़ी हुई छूट सीमा को पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है।

ITAT ने 12 जून 2026 के अपने आदेश में कहा कि PSU (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग) और प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर्स के रिटायर हो चुके कर्मचारियों को छूट की इस बढ़ी हुई सीमा का फायदा मिल सकता है। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्होंने 3 लाख रुपए से ज्यादा के लीव एनकैशमेंट पर पहले ही टैक्स चुका दिया था।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने 2023 के अपने नोटिफिकेशन में साफ किया है कि यह बढ़ी हुई छूट रिटायरमेंट के समय जमा 'अर्न्ड लीव' (कमाई गई छुट्टी) पर लागू होती है, चाहे रिटायरमेंट सुपरएनुएशन (सेवा-निवृत्ति की आयु पूरी होने) पर हुआ हो या किसी और वजह से। आइए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं...

लीव एनकैशमेंट पर ITAT का फैसला कैसे आया?

ITAT का यह फैसला ONGC के रिटायर्ड कर्मचारी वट्टिकुंडाला प्रभाकर राव के मामले से जुड़ा है। उन्हें वित्त वर्ष 2019-20 में रिटायरमेंट के समय लीव एनकैशमेंट के तौर पर 19।05 लाख रुपए मिले थे। असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय, राव ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 10(10AA)(ii) के तहत पूरी रकम पर छूट का दावा किया। हालांकि, बेंगलुरु में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर ने छूट को 3 लाख रुपए तक सीमित कर दिया और बाकी रकम पर टैक्स लगा दिया।

राव ने अपील की, लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (अपील्स) ने उनका दावा खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि असेसी को केवल 3,00,000 रुपए तक की छूट मिलती है, जब तक कि केंद्र सरकार किसी नोटिफिकेशन के जरिए इस सीमा को बढ़ा न दे, जो अभी तक नहीं किया गया है।

ITAT के सामने असेसी की अपील में 1,023 दिनों की देरी हुई। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने देरी को माफ कर दिया। ट्रिब्यूनल ने माना कि असेसी ईमानदारी और नियम का पालन करते हुए किसी कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार कर रहा था। यह इंतजार दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 8 नवंबर 2019 को कमल कुमार कालिया मामले में सरकार को नोटिस जारी करने के बाद से हो रहा था, जिसमें 3 लाख रुपए की छूट की सीमा को चुनौती दी गई थी।

अपस्टॉक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, रेवेन्यू के वकील ने तर्क दिया कि बढ़ी हुई छूट की सीमा केवल 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई थी। इसलिए असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए असेसी को इसका फायदा नहीं मिल सकता था। हालांकि, असेसी के वकील ने तर्क दिया कि नोटिफिकेशन "फायदेमंद और सुधार लाने वाला" था। वकील ने स्पष्टीकरण मेमोरैंडम की ओर भी इशारा किया, जिसमें कहा गया था कि इस बदलाव से किसी भी व्यक्ति पर बुरा असर नहीं पड़ेगा।

ITAT ने टैक्सपेयर के पक्ष में फैसला सुनाया

राव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, ITAT ने कहा कि छूट की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना लगभग दो दशकों के बाद एक "बड़ी बढ़ोतरी" थी। इस बदलाव का मकसद गैर-सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे को सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे के बराबर लाना और दोनों के बीच के अंतर को खत्म करना था।

ITAT ने आगे कहा कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जो प्रावधान फायदेमंद होते हैं और जिनका मकसद मुश्किलों को दूर करना होता है, उनकी व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए और उचित मामलों में उन्हें पिछली तारीख से लागू किया जाना चाहिए, खासकर तब जब इससे रेवेन्यू (राजस्व) के किसी पक्के अधिकार पर बुरा असर न पड़ रहा हो।

ट्रिब्यूनल ने गौर किया कि नोटिफिकेशन के साथ दिए गए स्पष्टीकरण मेमोरेंडम में कहा गया था कि इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि इस नोटिफिकेशन को पिछली तारीख से लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर बुरा असर नहीं पड़ रहा है।

ITAT को टैक्सपेयर की इस दलील में "काफी दम" लगा कि नोटिफिकेशन की तारीख से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बढ़ी हुई छूट न देने से "एक ही स्थिति वाले कर्मचारियों के बीच – जो नोटिफिकेशन की तारीख से पहले और बाद में रिटायर हुए – एक अनुचित और बनावटी अंतर पैदा होगा, जिससे संशोधन का मूल मकसद ही खत्म हो जाएगा।

त्योहारों से पहले कंपनियों और हलवाइयों को झटका! सरकार का चीनी स्टॉक लिमिट में राहत देने से इनकार

सरकार ने चीनी का अतिरिक्त स्टॉक बेचने के लिए और समय की मांग को ठुकरा दिया है। चीनी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को अब 31 अगस्त तक अपना अतिरिक्त स्टॉक बेचना होगा।

सरकार ने बिस्किट और ब्रेड बनाने वाली कंपनियों की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने स्टॉक रखने की तय सीमा से ज्यादा स्टॉक को बेचने के लिए और समय मांगा था। सरकार ने कंपनियों को आदेश दिया है कि वे 31 अगस्त तक अपना सारा अतिरिक्त स्टॉक बेच दें। हाल ही में स्टॉक रखने की समय-सीमा को 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। इसके तहत, बड़ी मात्रा में चीनी का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को अपनी सामान्य जरूरत का सिर्फ 15 दिन का स्टॉक ही रखने की इजाजत है। खाद्य सचिव के साथ हुई बैठक में देश की कुछ बड़ी कंपनियों ने चेतावनी दी कि अगर वे अभी अपना स्टॉक बेच देती हैं और बाद में बाजार से चीनी खरीदती हैं, तो चीनी की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती हैं। उन्होंने सप्लाई कम होने पर एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे करने में आने वाली दिक्कतों पर भी चिंता जताई।

कंपनियों आरोपों को किया खारिज

ट्रेड अधिकारियों का कहना है कि अगर यह स्टॉक 31 अगस्त तक बाजार में वापस आ जाता है, तो इससे चीनी की कीमतें काफी कम हो सकती हैं। यह कदम 'इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन' (ISMA) के उन आरोपों के बाद उठाया गया है जिनमें कहा गया था कि बड़ी मात्रा में चीनी इस्तेमाल करने वाली कंपनियों ने चीनी का स्टॉक जमा करके रखा है। कंपनियों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

बिस्किट बनाने वाली एक लिस्टेड कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि हम अपनी प्रोडक्शन की जरूरतों के हिसाब से सीज़नल स्टॉक जमा करते हैं, न कि दोबारा बेचने या सट्टेबाज़ी के लिए। मैं साबित कर सकता हूं कि हमारे द्वारा खरीदी गई चीनी का हर किलोग्राम बिस्किट या कैंडी जैसे खाने-पीने के सामान में बदल दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि हम चीनी को बिस्किट जैसे खाने-पीने के सामान में बदलते हैं, जिन्हें आम लोग खाते हैं। अगर हम अभी अपनी हेज्ड (hedged) चीनी बेच देते हैं, तो 15 दिन बाद हम फिर से तेजी से बाजार में लौटेंगे, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बन सकता है। कुछ FMCG कंपनियां इस बात से खुश हैं कि सरकार के इस कदम से कीमतों में उतार-चढ़ाव कम हो सकता है, क्योंकि कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की तुलना में उतार-चढ़ाव उनके कारोबार के लिए ज्यादा नुकसानदायक होता है।

सही है सरकार का फैसला

पार्ले के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मयंक शाह ने ईटी की रिपोर्ट में कहा कि हम सरकारी नियमों के अनुसार स्टॉक रखते हैं। हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर हम चाहें भी, तो ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं कर सकते। सरकार के कदम के बाद चीनी की कीमतें कम हुई हैं। इस कदम से सट्टेबाज़ी करने वालों पर लगाम लगेगी। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि अगर थोक खरीदार स्टॉक रखने की सीमा का पालन करते हैं, तो चीनी की कीमतें और कम हो सकती हैं। चीनी उद्योग के सीनियर एनालिस्ट जीके सूद ने कहा कि अगर थोक खरीदार कानूनी सीमा से ज्यादा स्टॉक को बेच देते हैं, तो हमें बाज़ार में लगभग 3-4 लाख टन अतिरिक्त चीनी मिल सकती है।

करना पड़ सकता है मुश्किलों का सामना

कुछ एनालिस्ट्स ने बताया कि MNC FMCG और फार्मा कंपनियों को, जिन्हें मंजूरशुदा मिलों से खास ग्रेड की चीनी की जरूरत होती है, समय पर सप्लाई पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इंडस्ट्री बॉडी ISMA ने दावा किया था कि ट्रेडर्स और बड़े खरीदारों ने सट्टेबाजी के लिए खरीदारी की, जिससे बाजार में चीनी की बनावटी कमी पैदा हो गई। सूद ने कहा कि व्यापारिक संगठन का सारा दोष अपने ग्राहकों पर मढ़ना व्यापारिक नैतिकता के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में चीनी व्यापारियों के यहां हुई छापेमारी से व्यापारी समुदाय में हड़कंप मच गया है।

नेपाल-चीन में 1500 के करीब लोग लापता: इनमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक शामिल, मृतकों का आंकड़ा 175 हुआ

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल त्रासदी की भयावहता कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें नेपाल और चीन में 1500 के करीब लोग लापता हैं। जिनमें तिब्बत में 588 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। वहीं नेपाल सरकार ने कहा है कि उनके वहां 800 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक शामिल हैं।

नेपाल के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कहना है कि अचानक आई बाढ़ के बाद 826 लोग संपर्क से बाहर हैं। इनमें 579 पर्यटक शामिल हैं। लापता लोगों में नेपाली सशस्त्र बलों के 85 जवान भी शामिल हैं। वहीं विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 162 स्टाफ सदस्यों के बारे में भी कुछ पता नहीं चल सका है।

नेपाल सरकार ने कहा कि विदेशी नागरिकों सहित सैकड़ों लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बुधवार देर शाम जारी एक बयान में, प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि नेपाल सेना के 44 जवान, विभिन्न पुलिस चौकियों पर तैनात नेपाल पुलिस के 28 जवान और आपदा ग्रस्त क्षेत्र में तैनात 13 सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के जवानों से संपर्क नहीं हो पाया है। वहीं नेपाल विदेश मंत्रालय ने 300 से ज्यादा भारतीयों के लापता होने की पुष्टि की है।

तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने जताया दुख

तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने नेपाल के रसुवा इलाके और तिब्बत के कीरोंग में आई विनाशकारी बाढ़ से हुई जनहानि पर दुख जताया है। गुरुवार को उन्होंने एक बयान जारी कर अपनी भावनाएं व्यक्त की। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने एक बयान में कहा, 'नेपाल के रसुवा क्षेत्र और तिब्बत के कीरोंग में विनाशकारी बाढ़ के बारे में जानकर मुझे दुख हुआ है। इस आपदा की वजह से कई लोगों ने जान गंवाई और भारी नुकसान हुआ। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और शोक संतप्त और इस त्रासदी पीड़ित सभी लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति और हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।'

दलाई लामा ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि जहां भी संभव हो, उचित फॉलोअप उपाय किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी आपदाएं दोबारा न हों।' तिब्बती क्षेत्र से होते हुए बाढ़ सीमा पार भोटेकोशी नदी पहुंच गई, और नेपाल में विनाश का निशान छोड़ गई।

भूकंप नहीं, ग्लेशियर टूटने से आई तबाही

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने एक बयान में साफ किया है कि नेपाल में आई तबाही का कारण भूकंप नहीं था। गौरतलब है कि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि भूकंप के चलते तिब्बत में ग्लेशियर टूटा, जिससे नेपाल-चीन में अचानक बाढ़ आई। हालांकि अब यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने साफ कर दिया है कि भूकंप नहीं आया था। ग्लेशियर के टूटने से भूकंप जैसे झटके महसूस हुए। ग्लेशियर टूटने से जो भूकंपीय कंपन हुई, उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई है।

कैंसर मरीजों के लिए राहत, अमेरिका में दवा को मिली मंजूरी...38 लाख रुपये में एक महीने की डोज

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने रिवोल्यूशन मेडिसिन्स की नई दवा 'रासोंक' को मेटास्टैटिक पैंक्रियाटिक कैंसर के इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। एक बड़े ट्रायल में ये दवा एडवांस्ड स्टेज के मरीजों के जीवित रहने की दर को लगभग दोगुना करने में सफल रही है। दिन में एक बार ली जाने वाली यह गोली उन मरीजों के लिए है जिनका पहले इलाज हो चुका है या जो कीमोथेरेपी नहीं ले सकते। कंपनी ने इसकी 30 दिन की सप्लाई की कीमत 39,800 डॉलर तय की है, जो मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से करीब 38 लाख रुपये बैठती है। महंगी होने के बावजूद कंपनी ने मरीजों के लिए फाइनेंशियल मदद का भी ऐलान किया है।

कैलिफोर्निया के फुलर्टन की 88 साल की बारबरा एंडेस ने एक साल की कीमोथेरेपी के बाद जुलाई में ये दवा शुरू की। उन्होंने बताया कि गोली की वजह से वे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां फिर से शुरू कर पाईं और जी मिचलाने तथा थकान की समस्या काफी कम हो गई। एंडेस ने कहा, ये दवा अब उन हजारों पीड़ितों के लिए उपलब्ध होगी। ये किसी वरदान से कम नहीं है। ये दवा एफडीए की नई एक्सपेडाइटेड रिव्यू प्रक्रिया का हिस्सा थी, जिसमें मंजूरी का समय सामान्य 10-12 महीनों से घटाकर 1-2 महीने कर दिया गया। रिवोल्यूशन के सीईओ मार्क गोल्डस्मिथ ने कहा, यह मंजूरी पैंक्रियाटिक कैंसर, खासकर आरएएस-ड्रिवन बीमारी पर एक दशक से ज्यादा के काम को सही साबित करती है। ये मेडिकल साइंस की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक थी।

ईरान के तेल और करेंसी पर गहरा संकट, पेट्रोल पंप हो रहे बंद, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 2 मिलियन रियाल

तेल अवीव, एजेंसी। युद्ध में किसी देश का भला नहीं होता है यह सिर्फ एक वाक्य भर नहीं है सच्चाई है। सच्चाई उन देशों की जो लंबे समय तक जंग में उलझे रहते हैं। ईरान-इजराइल और अमेरिका की जंग से ईरान को इकोनॉमी को तगड़ा डेंट लगा है। युद्ध के चलते लगे प्रतिबंधों ने देश की करेंसी रियाल को निचते स्तर पहुंचा दिया है। डॉलर के मुकाबले रियाल 2 मिलियन के बराबर पहुंच गया है। बीते एक दशक से ही अपने परमाणु प्रयोगों के चलते अमेरिका से सेंशन झेल रहे देश की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। करेंसी रसातल में जा रही है और महंगाई चरम पर है। आलम ये है कि तेहरान की पेट्रोल पंप पर तेल नहीं है। पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। देश में करीब डेली 1।5 करोड़ लीटर पेट्रोल की कमी पड़ रही है। साथ ही रोजमर्जा के सामान की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आइए डिटेल में ईरान के इस इकोनॉमिक क्राइसिस के समझते हैं।

ईरान में पेट्रोल की कमी से सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। ईरान रोज करीब 12 करोड़ लीटर पेट्रोल का उत्पादन करता है, जबकि खपत करीब 13।5 करोड़ लीटर है। यानी रोजाना 1।4-1।5 करोड़ लीटर की कमी है। पहले इस कमी का करीब आधा हिस्सा आयात से पूरा होता था, जिसमें रूस से मिलने वाली ईंधन सप्लाई भी शामिल थी। लेकिन अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी, रूस की रिफाइनरियों पर यूक्रेनी हमलों और कैस्पियन सागर के रास्ते की सप्लाई बंद होने से आयात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ईरान के सहयोगी देशों और पड़ोसियों से वैकल्पिक ईंधन सप्लाई हासिल करने की कोशिशें भी अभी तक सफल नहीं हुई हैं।

पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर

पेट्रोल संकट का असर राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में दिख रहा है। कुछ पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं और कई जगह लंबी कतारें लग रही हैं। अधिकारियों ने दूसरे प्रांतों से पेट्रोल मंगाकर तेहरान के कुछ पंप दोबारा खुलवाए हैं, लेकिन दर्जनों पंपों पर बंद होने का खतरा बना हुआ है। पेट्रोल की कमी से Snapp और Tapsi जैसी राइड-हेलिंग सेवाओं का किराया भी बढ़ गया है। एक नागरिक के मुताबिक, Snapp की सामान्य यात्रा का किराया पिछले महीने के 10 लाख रियाल से बढ़कर 32 लाख रियाल हो गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर ईंधन की सप्लाई सीमित कर रही है, ताकि आगे पेट्रोल की कीमत बढ़ाने को लेकर लोगों को तैयार किया जा सके।

ईरान का करना पड़ता है तेल आयात

ईरान के पास दुनिया के बड़े कच्चे तेल भंडार हैं, लेकिन उसकी रिफाइनिंग क्षमता घरेलू जरूरत के मुकाबले कम है। ऐसे में पेट्रोल आयात करना पड़ता है, लेकिन अमेरिकी नाकाबंदी और प्रतिबंधों के कारण आयात प्रभावित हुआ है। युद्ध के दौरान रिफाइनरी और ईंधन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान ने भी संकट बढ़ाया है। पेट्रोल की कमी की आशंका में लोगों की पैनिक बाइंग ने दबाव और बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि पेट्रोल कोटा कम किया जा सकता है और कोटे से ज्यादा खरीद पर कीमत बढ़ सकती है। हालांकि, सरकारी अधिकारियों का कहना है कि सप्लाई सिस्टम पूरी तरह ठप नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में स्थिति सुधर सकती है।

ईरान में करेंसी की लगातार गिरने की वजह से मुद्रास्फीति का संकट आ गया है। अलजजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबित, 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध से पहले देश में 2 मिलियन रियाल में लोगों को 4 किलो टमाटर, आधा किलो चिकन और एक लीटर से थोड़ा कम खाने का तेल मिल सकता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इतने में इसका कुछ आधा ही सामान खरीदा जा सकता है। टमाटर की कीमत 71 प्रतिशत बढ़ गई है। वहीं, चिकेन 74 प्रतिशत तो खाने का तेल 177 प्रतिशत महंगा हो गया है।

दवाओं की कीमतों में भी तगड़ा उछाल

खाने-पीने के सामान के दाम आसमान छू ही रहे हैं। इसके अलावा ईरान में जीवनरक्षी दवाओं की कीमतों में भयंकर उछाल देखने को मिला है। मिसाल के तौर पर डायबिटीज के उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन के दाम 642 प्रतिशत बढ़ गए हैं। पैरासिटामोल जैसी दवाओं की कीमतों में 93 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, शिशुओं के आहार में भी तगड़ा उछाल आया है। सरकार की ओर से इस पर काफी सब्सिडी दी जाती है। मगर इस युद्ध ने उनकी कीमत भी 95 प्रतिशत तक बढ़ा दी है।

ईरान का मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस सिर्फ पेट्रोल या महंगाई तक सीमित नहीं है। युद्ध, अमेरिकी प्रतिबंध, कमजोर रियाल और सप्लाई में रुकावट ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो ईंधन और जरूरी सामान की कमी के साथ महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। यानी दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल ईरान आज अपनी ही घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

30 दिन की पैरोल लेकर भागे कैदी ने की सरकारी नौकरी, मिला 'बेस्ट टीचर' का अवॉर्ड, 40 साल बाद गिरफ्तार

हैदराबाद। हैदराबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति को 40 साल पहले हत्या का दोषी पाया गया, उसे सजा भी मिली, लेकिन जब वो पैरोल पर कुछ दिनों के लिए बाहर आया, तो पैरोल तोड़कर भाग गया। इस मामले में यह बात यहीं तक हैरान करने वाली नहीं है। इस मामले में बात सामने आई है कि व्यक्ति के पैरोल तोड़कर भागने के बाद वो सरकारी टीचर भी बन गया। यहां तक कि उसने बेस्ट टीचर का अवॉर्ड भी जीता। संडेला वीरन्ना, जिसकी उम्र 70 साल के करीब है, उसे 1970 के दशक के आखिर में एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। इस मामले में आरोपी को 1983 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई, लेकिन सजा शुरू होने के छह महीने बाद ही वीरन्ना को पैरोल पर रिहा कर दिया गया, लेकिन पैरोल पर रिहा होने के बाद वो कभी जेल वापस नहीं लौटा। आखिरकार मई 2024 में तेलंगाना जेल विभाग की एक स्पेशल टास्क फोर्स ने महबूबाबाद पुलिस की मदद से उसे ढूंढ निकाला और चेर्लापल्ली सेंट्रल जेल में डाल दिया। संडेला वीरन्ना की पत्नी संडेला चरम्मा ने हाल ही में मेडिकल और मानवीय आधार पर लगातार जेल में कैद और पिछले तीन सालों से पैरोल न मिलने को तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

अनुराग ठाकुर ने हिमाचल लॉटरी को बताया राहुल गांधी का 'फटा-फट' मॉडल, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़

नई दिल्ली। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रस्तावित लॉटरी सिस्टम की आलोचना करते हुए कहा कि यह कदम राज्य के युवाओं और निवासियों के लिए नुकसानदेह होगा। इस मुद्दे पर बात करते हुए ठाकुर ने दावा किया कि राहुल गांधी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को राज्य के भोले-भाले लोगों का पैसा हड़पने के लिए 'फटा-फट' मॉडल दिया है – खासकर लॉटरी सिस्टम के ज़रिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी, दोनों सरकारों ने पहले लॉटरी पर रोक लगाई थी ताकि युवाओं को जुए की लत का शिकार होने से बचाया जा सके।

ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी, दोनों सरकारों ने पहले लॉटरी पर रोक लगाई थी क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि राज्य के युवा जुए की लत या बुराई का शिकार बनें। लेकिन आज, राहुल गांधी हिमाचल के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने का भी आरोप लगाया, जिनमें पांच लाख सरकारी नौकरियां देना और महिलाओं को तुरंत 1,500 रुपये की आर्थिक मदद देना शामिल था। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान 5 लाख सरकारी नौकरियां देने और महिलाओं के खातों में तुरंत 1,500 रुपये जमा करने का वादा किया गया था; लेकिन, वह वादा अब टूट चुका है और एक नाकाम मॉडल बनकर रह गया है। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई और बताया कि हिमाचल प्रदेश पर 1.10 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का कर्ज है और खबरों के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति कर्ज सबसे ज़्यादा यहीं है। ठाकुर ने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश पर 1.10 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का कर्ज है। हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्ज देश में सबसे ज़्यादा है, और नाकाबिल कांग्रेस सरकार ने बार-बार सेस और टैक्स लगाकर गरीब, भोली-भाली जनता का लगातार शोषण किया है। लॉटरी शुरू करने के पीछे की वजह पर सवाल उठाते हुए, ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखू से इस प्रस्ताव को वापस लेने की अपील की। उन्होंने पूछा कि लॉटरी क्यों? ऐसी सोच क्यों रखना जो राज्य के युवाओं और लोगों के भविष्य को अंधेरे में धकेल दे – और यह सब सिर्फ़ जनता का पैसा तेज़ी से निकालने के लिए? ठाकुर ने चेतावनी दी कि अगर लॉटरी सिस्टम लागू किया गया तो बीजेपी और हिमाचल प्रदेश के युवा विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि यह वही मॉडल है जिसे राहुल गांधी ने पेश किया है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि वे इसे तुरंत रद्द करें; वरना, बीजेपी और राज्य के युवा सड़कों पर उतरेंगे ताकि यह पक्का किया जा सके कि हिमाचल प्रदेश में लॉटरी सिस्टम लागू न हो।

बिग बॉस 20 में एंट्री नहीं लेंगी शिवांगी जोशी, वायरल वीडियो को बताया फेक

इंडिया के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 20 को लेकर इन दिनों काफी चर्चा है। शो जल्द ही दर्शकों को एंटरटेन करने आ रहा है और शो को लेकर कई कंटेस्टेंट्स के नाम भी सामने आ रहे हैं। इनमें टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी का नाम भी चर्चा में था। हालांकि, शिवांगी ने इन खबरों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि वो शो का हिस्सा नहीं हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो फेक है।

शिवांगी जोशी ने बिग बॉग 20 में एंट्री की खबरों पर रिएक्ट किया है और इसे पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा, मुझे पता चला है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गलत तरीके से दावा किया जा रहा है कि मैं बिग बॉस में हिस्सा ले रहा हूं। मैं क्लियर करना चाहती हूं कि मैं बिग बॉस 20 में पार्टीसिपेट नहीं कर रही हूं और वो वीडियो पूरी तरह से फेक है।

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि शिवांगी जोशी बिग बॉस 20 की कंफर्म कंटेस्टेंट हैं। हालांकि अब एक्ट्रेस ने रूमर्स को खारिज कर दिया है।

बता दें, सलमान खान का शो बिग बॉस 20 6 सितंबर से कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर आएगा। शो को लेकर काफी बज बना हुआ है।

शिवांगी जोशी हाल ही में रियलिटी शो लॉक अप 2 में नजर आई थीं, जहां उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। शो के दौरान उनका नाम हर्ष चोपड़ा के साथ भी जोड़ा गया था, हालांकि दोनों ने साफ किया था कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। शिवांगी शो की रनर-अप रही थीं, जबकि श्रेया कालरा ने ट्रॉफी अपने नाम की थी। वहीं, फराह खान और रितेश देशमुख ने शो को होस्ट किया था।

प्रेग्नेंट सामंथा ने खास डिस्क्लेमर के साथ शेयर किया वर्कआउट वीडियो, बोलीं– 'कम जोर लगाएं, शरीर की सुनें'

एक्ट्रेस सामंथा ने प्रेग्नेंसी के दौरान अपने वर्कआउट रूटीन की झलक फैंस के साथ शेयर की है। उन्होंने इसके साथ एक खास डिस्क्लेमर भी दिया है। जानिए वीडियो में क्या कुछ है खास।

39 साल की सामंथा ने यह भी बताया कि प्रेग्नेंसी के बाद फिटनेस को लेकर उनका नजरिया बदल गया है। अब वह खुद को लगातार ज्यादा पुश करने के बजाय जरूरत पड़ने पर रुकना और अपने शरीर की बात सुनना ज्यादा जरूरी समझती हैं।

सामंथा ने अपने वर्कआउट के कई वीडियो शेयर किए। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, 'आजकल ट्रेनिंग का तरीका अलग है। ज्यादा जोर लगाने से ज्यादा जरूरी है कि शरीर की बात सुनी जाए।' एक दूसरे स्लाइड में वह डेडलिफ्ट करती नजर आईं। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'जब आप अपनी क्षमता के 70 फीसदी पर ही रुक जाते हैं।'

एक अन्य तस्वीर में वह डंबल उठाती दिखाई दीं। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'कुछ दिन मैं खुद को मजबूत महसूस करती हूं। कुछ दिन मैं एक्सरसाइज में बदलाव करती हूं।'

डॉक्टर की सलाह के बाद कर रही हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग

सामंथा ने अपने कैप्शन में बताया कि डॉक्टर से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने प्रेग्नेंसी के दौरान भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जारी रखी है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके ट्रेनर प्रीनेटल ट्रेनिंग के लिए सर्टिफाइड हैं और उनके वर्कआउट को उनकी बॉडी, अनुभव और प्रेग्नेंसी के हिसाब से बदला गया है।

उन्होंने लिखा, 'एक छोटा सा डिस्क्लेमर: मैंने काफी समय से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है और डॉक्टर की अनुमति के बाद प्रेग्नेंसी के दौरान भी इसे जारी रखा है। मेरे ट्रेनर भी प्रीनेटल ट्रेनिंग के लिए सर्टिफाइड हैं और यहां दिखने वाली हर एक्सरसाइज को मेरी बॉडी, मेरे अनुभव और मेरी प्रेग्नेंसी के हिसाब से बदला गया है।'

सामंथा ने आगे लोगों को सलाह दी कि हर प्रेग्नेंसी अलग होती है, इसलिए उनके वर्कआउट को देखकर कोई अपनी एक्सरसाइज तय न करे। उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंसी के दौरान एक्सरसाइज करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें और किसी योग्य ट्रेनर के साथ ही वर्कआउट करें।

मां इंटी बंगारम में नजर आई थीं सामंथा

वर्कफ्रंट की बात करें तो सामंथा हाल ही में तेलुगु फिल्म मां इंटी बंगारम में नजर आई थीं।

इस फिल्म को राज निदिमोरु ने लिखा और बनाया था।

फिल्म के सक्सेस सेलिब्रेशन के दौरान सामंथा पहली बार बेबी बंप के साथ पब्लिक में नजर आई थीं।

इसके बाद उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लग गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'द फैमिली मैन' एक्ट्रेस इस साल के आखिर तक अपने पहले बच्चे का स्वागत कर सकती हैं।

हैवान का ट्रेलर जारी, सैफ अली खान का दिखा संघर्ष, अक्षय कुमार की हैवानियत ने उड़ाए होश

अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर हैवान का ट्रेलर आखिरकार आ गया है. प्रियदर्शन डायरेक्टेड यह फिल्म एक डार्क और दिलचस्प थ्रिलर का वादा करती है. ट्रेलर फिल्म की अनप्रिडिक्टेबल दुनिया की एक झलक दिखाता है. साथ ही दोनों लीड एक्टर्स के बीच चूहे-बिल्ली की लड़ाई भी दिखाई जाती है.

अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर हैवान का ट्रेलर अपलोड किया है और कैप्शन में लिखा, टीजर में साया देख चुके हो, अब हैवान से मिलो. ट्रेलर में अक्षय कुमार हैवान के रोल में खूंखार अवतार में दिख रहे हैं, जबकि सैफ अली खान एक अंधे आदमी का रोल कर रहे हैं, जो शायद एक सिंगल फादर है.

2 मिनट 34 सेकंड के ट्रेलर में डरावना माहौल दिखाया गया है. इसकी शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो मदद के लिए बेताब होकर रो रहा है और मौत की तरफ धकेले जाने से पहले अपनी जान की भीख मांग रहा है. परेशान करने वाली शुरुआत तुरंत आगे की कहानी का टोन सेट कर देती है.

ट्रेलर में आगे सैफ का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका कैरेक्टर सामने आने वाले रहस्य के सेंटर में लगता है. इसके बाद अक्षय एक नेगेटिव रोल में एक डरावने और खतरनाक आदमी के रोल में दिखते हैं. दोनों कैरेक्टर इस खतरनाक गेम में एक-दूसरे से भिड़ते हुए लगते हैं.

हैवान के ट्रेलर में जो बात सबसे अलग है, वह है सैफ का किरदार. एक्टर ने एक अंधे आदमी का रोल किया है, जो अक्षय के साथ एक जानलेवा लड़ाई में फंस जाता है. किरदार की विकलांगता कहानी का एक अहम हिस्सा है, न कि सिर्फ किरदार की कोई पर्सनल खासियत. ट्रेलर में कहानी का ज्यादातर हिस्सा जानबूझकर छिपाकर रखा गया है, लेकिन यह दिखाता है कि शहर में कई मर्डर हो रहे हैं.

सैयामी खेर कहानी में एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर आती हैं, जो सभी हत्याओं की जांच कर रही हैं. सैफ के किरदार के शॉट्स के बीच, एक वॉइस-ओवर कहता है, अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना. यह लाइन सैफ के किरदार के आस-पास के रहस्य में एक और परत जोड़ती है और इशारा करती है कि वह शुरू में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा हो सकता है.

अक्षय कुमार और सैफ अली खान 17 साल बाद फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. 2008 में आई टशन उनकी आखिरी फिल्म थी. दोनों ने पहले मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और यह दिल्लगी (1994), तू चोर मैं सिपाही (1996) और कीमत (1998) जैसी फिल्मों में साथ काम किया है.

फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के अलावा, बोमन ईरानी, श्रेया पिलगांवकर, सैयामी खेर, राजपाल यादव, शारिब हाशमी, राजेश शर्मा, पहल चौधरी और मनोज जोशी भी है. वेंकट के नारायण और शैलजा देसाई फेन द्वारा केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस की गई हैवान 11 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी.

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com